कायम कर रहे हैं । आज तक भी इस तरह नहीं हुआ । अगर कोई चेंज करना हो, तो यूनिमाला तो वह किया जा सकता है लेकिन केवल मंत्री महोदय के कहने से ऐसा करना एक बहुत खराब प्रिसिडेंट होगा ।

MR. SPEAKER: I agree with you. Instead of taking a decision now, this particlar item may be referred back to the Business Advisory Committee for further reconsideration. I hope the House is agreeable to the rest of the Report. I will now put it to the vote of the House. The question is:

"That this House agrees with the Nineteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd July, 1968 subject to the modification that items (6) and (7) of the Report be referred back to the Committee for reconsideration."

The motion was adopted.

12.56 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

BORDER SECURITY FORCE BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Y. B. Chavan on the 23rd July, 1968, namely:—

"That the Bill to provide for the constitution a nd regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith, be taken into consideration."

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष जी, जिन भावनाओं से यह विधेयक संसद् के सामने रखा गया है मैं उस का स्वागत करता हूं । हमें मालूम है कि जो हमारे देश की सीमाएं हैं उन पर बहुत गड़बड़ है । आज से नहीं, पिछले कई सालों से गड़बड़ है और तरह की तरह की गड़बड़ियां वहां पर हैं । पाकिस्तान की तरफ से अलग गड़बड़ है, चीन की तरफ से अलग गड़बड़ है और हमारे ही देश के कुछ लोग जो अपने आप को हिन्दुस्तानी कहते हैं पर जिन की वफादारी शायद हमारे देश के साथ उतनी नहीं जितनी दूसरे देशों के साथ है उन की तरफ से भी काफी गड़बड़ है । कुछ स्मगलर्स हैं, कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स हैं यह सारी समस्या मिला कर के काफी पेचीदा स्थिति पैदा है । अब उसको रोकने के लिए यह विधेयक संसद् के सामने आया । उससे स्थिति का मुकाबिला अच्छी प्रकार से होगा इस आशा के साथ मैंने इस का स्वागत किया है । मैंने उपाध्यक्ष जी, एक संशोधन भी दिया है जिस में मैंने यह मांग की है कि गृह-मंत्री से कि वह इस को सेलेक्ट कमेटी में भेज दें । उसके कई कारण हैं । मैं यह समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है कि जिस के बारे में अच्छी प्रकार से विस्तारपूर्वक विचार होना चाहिए । उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी क्योंकि मैं समझता हूं कि वह एक अर्द्ध-सैनिक स्थिति में है, सेमी मिलटरी स्टेट्स उस का है जिस की ट्रेनिंग जिन का पनिशमेंट, जैसा खुद माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा बहुत सख्त है, इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब आप उनकी ट्रेनिंग अच्छी करना चाहते हैं, जब अगर वह कानून को या अनुशासन को भंग करें तो उनको कड़ी सजा देना चाहते हैं तो आप ने उनकी सर्विस कंडीशंस कैसी रखी है । उन की सर्विस कंडीशंस भी सेना के मुताबिक ही होनी चाहिएं, उसके बारे में में भी हमें जांच करनी पड़ेगी । इसी प्रकार किस तरह से अदालतों का निर्माण हो यह भी सारी चीजें इतनी बड़ी और व्यापक हैं कि जिन के बारे में सोचना जरूरी है ।

[श्री कंवरलाल गुप्त]

एक चीज की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है इस के अन्दर कुछ काम्पलीकेशंस भी हो सकते हैं । पेचीदगियां क्या हो सकतीं हैं कि एक तो यह कि कुछ लोगों को यह भी डर हो सकता है कि केन्द्र अनावश्यक हस्तक्षेप राज्य सरकारों में कर सकता है और जो पुलिस का दायरा है उसके ऊपर भी कुठाराघात कर सकता है । अब इस के बारे में भी हमें कुछ सोचना होगा । इस की आड़ में जो ऐसी सरकारें हैं जो केन्द्र को कमजोर करना चाहतीं हैं वह कुछ और बातें भी गड़बड़ कर सकती हैं । मैंने इस बात का इसलिये समर्थन किया कि मैं और मेरी पार्टी हमेशा चाहे वह केन्द्र कांग्रेस के हाथ में हो या किसी के हाथ में क्यों न हो जब तक वह राष्ट्र के हितों की रक्षा करता है, हमारी इच्छा यह है कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिये और इसलिए मैंने इस का स्वागत किया । लेकिन हमें इस बात को जरूर देखना चाहिये । मैं आप के जरिए मंत्री महोदय से कहूंगा कि किसी प्रकार से इस प्रकार की भावना किसी राज्य सरकार को न हो कि किसी तरह से भी उस में हस्तक्षेप किया जा रहा है और दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिये कि अगर कोई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर के विदेशों के साथ अपना सम्पर्क स्थापित करना चाहती हैं या देश में गड़बड़ पैदा करना चाहती हैं, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं चाहे वह कोई भी हों, नाम देने की जरूरत नहीं हैं, सब लोग इसको जानते ही हैं, उसके बारे में भी सतर्क होने की जरूरत है । राज्य की पुलिस का और इस बार्डर पुलिस का क्या सम्बन्ध है यह स्पष्टीकरण करने की जरूरत है मुझे याद है कि बंगाल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने इस पर एतराज किया है । मैं तो उसे कम्यूनिस्ट ही कहता हूं । नाम उस का संयुक्त मोर्चा सरकार लेकिन असल में कम्युनिस्ट सरकार यह थी, उसने इस पर एतराज किया था और इसी प्रकार से मैंने यह भी सुना है कि पंजाब सरकार ने भी इस पर एतराज किया था । इसलिए माननीय गृह मंत्री से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि किस प्रकार के संबंध राज्य की पुलिस के और इसके होने चाहिये इस के बारे में भी विचार करना चाहिये । इस प्रकार की भावना किसी की न बनें कि किस प्रकार से भी हस्तक्षेप किया जा रहा है ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं मैं उस नुमायश को देखने के लिए गया था, उपाध्यक्ष जी, शायद आप भी उसको देखने के लिए गये होंगे । वहां पर मैंने यह देखा— मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन जो थोड़ी बहुत नालिज मेरी है उस के आधार पर कह रहा हूं कि मिलिट्री के जो ओबसलीट-आर्म्ज हैं, आप ने वे आर्म्ज बार्डर पुलिस को दे रखे हैं । मैंने उनसे पूछा कि आपके ये जो हथियार हैं, ये तो अब आउट-आफ-डेट हो गये हैं, इन से नागाओं, मिजो और पाकिस्तानी सेना के लोग जो रजाकारों की शक्ल में आते हैं, उन का मुकाबिला करना आपकी पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा । मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उसे में सन्देह नहीं कि यह फोर्स बहुत अच्छी चीज है, 60—70 हजार लोग हमारी इस बार्डर पुलिस में हैं, लेकिन उन को आप अच्छे और माडर्न वैपन्ज दीजिये, उन को अच्छी ट्रेनिंग्ज दीजिये ताकि वे किसी भी परिस्थिति में डट कर मुकाबला कर सकें । मेरी इन्फार्मेशन तो यह है कि उन के पास बाइनोकुलर्ज भी नहीं हैं .....

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह आप क्य कह रहे हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप मालूम कर लीजिये । मैंने मालूम करके ऐसा कहा है ।

वाइनोकुलर्ज़ उन के पास जितने होने चाहियें, उसका केवल 5 प्रतिशत हैं ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इतने शानदार देश की कमजोरी बता रहे हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : कमजोरी नहीं बता रहा हूं, अगर ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो वहां पर हरियाणा के नौजवान मारे जायेंगे । इसलिये, उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को देखें कि मार्डन आर्म्ज उनके पास हैं या नहीं हैं, पूरे आर्म्ज़ उनके पास हैं या नहीं हैं, पूरी सुविधायें उनके पास हैं या नहीं हैं ।

तीसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी प्रकार से होनी चाहिये। मैंने सुना है कि अभी अभी कुछ मिलिट्री आफिसर्ज़ उनके यहां आये हैं । यह बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूं । अच्छा अनुशासन, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे आर्म्ज़-यदि इस प्रकार का स्टेण्डर्ड रहा तो मैं समझता हूं कि बहुत ठीक होगा ।

चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो सैन्सिटिव बार्डर है, केवल पुलिस के सहारे उसकी रक्षा नहीं होगी । इसके लिए हमें कुछ और भी करना होगा । मेरे अपने खयाल से वहां पर जो रहने वाले हैं उनको भी आर्गनाइज किया जाय । आज हमारे देश की जो स्थिति है, उसमें बहुत जल्द तो मैं अपेक्षा नहीं करता कि हमारे बार्डर शान्त हो जायेंगे, इसमें कई साल लग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे साथ दुश्मनी करता है—चाहे हमारी सरकार पाकिस्तान के सैनिक हवाई जहाजों को लखनऊ उतरने दे, परन्तु पाकिस्तान हमारे साथ ऐसी दोस्ती करने वाला नहीं है । पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम जानते हैं, चीन कैसा बर्ताव कर रहा है, वह हम जानते हैं । ऐसी स्थिति में हमें इसको थोड़ा और मज़बूती से देखना होगा और केवल बार्डर पुलिस से वहां पर काम नहीं चलेगा । बार्डर्ज़ पर रहने वाले जो लोग हैं, हमें उनको आर्गेनाइज़ करना पड़ेगा ताकि वे हमारी पुलिस को सूचनायें दें, उनकी सहायता करें और अगर कहीं हमारी पुलिस की संख्या कम है तो हमें उनकी मदद भी मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये । चाहे डिसिप्लिंड फोर्स के नाम से थोड़े समय के लिये हमें उन लोगों को भी हथियार देने चाहियें । जो लोग विश्वस्त हैं, जिन लोगों को सरकार विश्वस्त मानती है, उनमें से छांट कर उन लोगों को हथियार देने चाहियें और वे लोग हमारी पुलिस की सहायता करें । उनका कोआर्डिनेशन होना चाहिये—हमारी बार्डर पुलिस के साथ, तो यह ज्यादा अच्छा होगा ।

मुझे याद है 1965 में जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तब राजस्थान बार्डर पर हमारी सेनाओं को यह भी मालूम नहीं था कि पानी का कुआं कहां है, यह रास्ता किधर जाता है, उनको उस जगह के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था और उनको बताने वाला भी कोई नहीं था । इसलिए ज्यादा ज़रूरी है कि वहां की जो आबादी है, उनके साथ हमारा सम्पर्क हो और उस आबादी के साथ हमारे सिपाही और हमारे पुलिस अधिकारी सम्बन्ध स्थापित कर सकें ।

पांचवीं चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो आब्जेक्टिव दिये गये हैं, उसमें यह लिखा गया है कि इण्डो-पाकिस्तान बार्डर पर ही यह फोर्स काम करेगी, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि केवल पाकिस्तान के साथ ही हमारा बार्डर नहीं है, चीन के साथ, तिब्बत के साथ बार्डर लगता है या जो हमारे समुद्र लगते हैं वहां पर भी ज़रूरी है कि यह सेना तैनात हो, यह पुलिस तैनात की जाय । इस काम के लिये इस पुलिस की संख्या थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिये । आज जिस तरह का स्मगलिंग होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, वह चीज़ इनकी सहायता से रोकी जानी चाहिये । मेरे ख्याल से अगर अच्छी ट्रेनिंग और मार्डन हथियार इनको

[श्री कंवर लाल गुप्त]

दिये गये तो जिस प्रकार की लार्ज स्केल पर स्मगलिंग होती है, उसको भी ये लोग रोक सकेंगे तथा बार्डर्ज पर जो लोग रहते हैं, उनके अन्दर भी सिक्योरिटी आयेगी ।

एक आखिरी सुझाव देकर मैं समाप्त करूंगा । बार्डर पर हमें कुछ मजबूत लोगों को बसाना चाहिये, खास तौर से जो रिटायर्ड पुलिस आफिसर्ज हैं, सेना के लोग हैंटरी-टोरियल आर्मी के लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, जिनको डिसिप्लिंड फोर्स कहा जा सकता है, जो अनुशासित हैं, ट्रेनिंग पाये हुए हैं, सरकार उनको मुफ्त में या बहुत थोड़े दामों पर जमीन दे, सुविधायें दे, तो वे लोग वहां पर बसाये जा सकते हैं और समय पाने पर वे लोग हमारी इस पुलिस की मदद कर सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं इसका स्वागत करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दें ताकि इस पर पूरी तरह से विचार किया जा सके, इसमें जो कमियां हैं उन पर मिलजुल कर विचार किया जा सकता है और उनको दूर किया जा सकता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yesterday, the provisional time allotted for this Bill was 2 hours, but now the time has been increased to 5 hours. I have got to accommodate about 15 Members who have sent slips to me here. I would like to ascertain the sense of the House about how much time we should have for the general discussion and how much for the other stages.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): My party has not spoken.

MR. DEPUTY-SPEAKER: 2½ hours are still left. How shall we divide the time as between the different stages? What is the sense of the House?

SHRI SAMAR GUHA: First, time should be allotted to the representatives of every party to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The debate should conclude about three hours from now, that is, at about 5 P.M. That should be clear.

SHRI Y. B. CHAVAN: The distribution should be 3 hours for the first reading and 2 hours for the other stages.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): One hour is enough for clause-by-clause discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If hon. Members would agree on one hour for the clauses, then I shall be able to accommodate more Members.

श्री झारखंडे राय (घोसी) : उपाध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि जेनरल डिबेट का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाय । इसके प्रिन्सिपल्स से विस्तार में चाहे किसी को मतभेद न हों, लेकिन इसके कुछ सिद्धान्तों पर बातें हो सकती हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसकी जेनरल डिबेट का समय बढ़ा दिया जाय, ताकि सब लोगों को एकोमोडेट किया जा सके ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yesterday, in the Business Advisory Committee all these considerations were there and they were placed before them. The time has been increased to five hours. To extend it further would be difficult. But I would suggest that we may have 2 hours for general discussion now and 1 hour for the clause-by-clause consideration. We shall begin the clause-by-clause discussion at 4 P.M.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): You are now

presuming that there shall be clause-by-clause discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not now, but at 4 P.M.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: I am talking about four o'clock also. All of us are of the opinion that this Bill should be referred to a Select Committee, and every speaker is suggesting that it should be referred to a Select Committee. If you would be pleased to give me ten minutes, I shall prove why it should go to a Select Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I understand that this question had been raised at the meeting of the Business Advisory Committee where the representatives from all parties were present.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: I was not present.

MR. DEPUTY-SPEAKER: And they have taken that decision. There are two motions at the consideration stage and the House will decide it. I cannot say anything more at this stage.

Now, Shrimati Ila Palchoudhuri.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): May I speak? I have asked for her permission to speak earlier.

MR. DEPUTY-SPEAKER: She is a new Member so far as this House is concerned, and, therefore, let the hon. Member show some chivalry.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar): Mr. Deputy-Speaker. Sir, I warmly welcome this Bill. I know the areas, where we are in the border, like West Bengal and, particularly, in my own district Nadia. how much we depend on the Border Security Forces. It is a fact that they are the first line of defence because it is only when something will happen that the Army will take over and it is they who are the first to take the brunt of whatever is to come. So, I have my full sympathy and full admiration for the work they do. The work they are supposed to do has been laid down in the Home Ministry's own Report and in the Bill itself. They are supposed to give a sense of security to the people in the border areas.

Yesterday, some of my friends opposite—I was surprised to hear—said that the police was immobilised during the United Front Government's regime. I quite imagine that because the United Front Government in West Bengal was dominated by Communists and they immobilised the police whenever there was any need to do so. Secondly, I do not suppose they want this Force to really function because, they would like the border to be open for their friends to come in. However, that is beside the point.

Sir, India has a border of actually 4000 miles and West Bengal has a border of 1350 miles out of that border. I understand that there is yet a shortage of 10,000 people whom the Border Security Force could absorb. I do not know if this figure is correct because—I am a new Member—this was out before the last bye-election. I understand that the Border Security Force can yet take another 10,000 people. In that case, I would suggest that Namasudras who have come over from East Pakistan and who are strong in physique and warlike in temperament could be tained and absorbed in some of the areas in the border forces. I hope the hon. Minister will consider this when he recruits men for the Border Security Force and puts them into training.

I have also another thing to point out that the Border Security people have done wonderful work in Bengal. They have caught in one year more than 3000 cases of infiltration and they have confiscated smuggled goods worth more than Rs. 2 lakhs. Their work has been admirable and dis-

[Shrimati Ila Palchoudhuri]

tinctions have been awarded to them, I think, there could have been more distinctions awarded to them. We should also have, like the Army Day and the Navy Day, the Border Security Force Day. That should be observed and that would create the liasion between the Border Security Force people and the people of the area.

Then, my hon. friend Shri Indrajit Gupta, remarked yesterday that the Border Security people very often like fresh eggs and chickens. I would like to say that everybody likes fresh eggs and chickens when they can get it. But the Bill provides for it as one of the offences, namely extortion of that kind of thing. That is duly covered. I do not think we need to be at all worried about that aspect.

Then, I would make an urgent plea for one think and that is that the conditions of the Border Security police may be the same as those of the Army in as many ways it is possible to do so. You call them a para-military organisation. Well, if they are a para-military organisation, then some of their amenities should be the same as it is with the Army because they do no less work than the Army.

About housing in the border, Sir, it should have every attention of the Government and, I hope the hon. Minister will look into it. I understand Rs. 3 crores have been sanctioned by the Centre for police housing. I wonder how much of this has been used for the Border Security Force housing?

About their families, I would like to say that there should be some arrangement for looking after their families when their men are out guarding our borders facing death.

There is one other point that I would like to make. When you are going to punish them like in any military court, there is going to be death punishment also. They are going to be treated like military in every respect except for their emoluments and all other amenities that the military is entitled to. The punishment is almost the same as what the military would undergo for the same offence. Here I would say that, when it comes to death punishment, they should have access to the Home Minister and he should be there to grant them pardon if it is possible to do so . . . (*Interruptions*) I hope, they will have every access to him because once it comes to a death sentence then there should be somebody to appeal to and he can be the Home Minister who has sponsored the scheme. I hope, he will be there to give them any advantage, any pardon, any leniency, that can save a life. I would earnestly plead for that.

Then, leave for 60 days should always be there because their work is full of danger and tension. They are the first line of defence. They will become the second line of defence only when the army takes over. It is very true of that little quotation that an army man wrote in his own note-book, which was besmeared by blood and was later rescued; he wrote:

> "I have a *rendezvous* with death.
>
> At some disputed barricade.
>
> If mid-night in some flaming town.
>
> When spring trips north again
>
> And I, to my pledged word, am true;
>
> I shall not miss that *rendezvous*."

I know that our border police will never miss their *rendezvous* and they deserve all our gratitude, all our admiration and every consideration from the Ministry that has sponsored this Bill.

I welcome this Bill warmly and I hope that the Border Security Police will grow from strength to strength and protect India.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): This Bill reminds us of the colossal follies of Partition and of over-zealous profession of Bhai-Bhaism. This has resulted in the exposure of all the borders of our country which had the natural physiographical protection which perhaps few countries in the world have the gift of having such security.

Now all our borders are exposed to our actual and potential enemies. Pressed as we are today, we have to look to our border security which is a must for every nation and particularly for a nation like ours which is endangered and which had actually been in danger twice in 20 years.

Although I am in a mood to welcome this Bill, but I would humbly say to the Home Minister whether he was consulted in all its aspects while this Bill was prepared. This Bill gives an impression that it has been drafted very hastily. If the idea of having border security force means the exalted duplication of our armed police forces carrying outmoded rifles, then the purpose of this Bill will be frustrated and it will create conflicts with the States.

It seems rather strange that the main objective of the Bill has been defined in a slipshod manner. I do not know whether it has been done intentionally. The reason is quite obvious, as Pakistan and others will immediately say something about it—I do not want to go into it in details. In this Bill, it has been said that there shall be an armed force of the Indian Union. But nowhere in this Bill the status and the task that will be assigned to this Security Force have been clearly defined. The objective is rather vague, confused, and not clearly laid down. Only in Chapter X, 'Miscellaneous', has the purpose of constituting this security force and the task that will be assigned to it been defined. What is that purpose? For the purpose of prevention of any offence punishable under the Passport (Entry into India) Act, 1920, the Registration of Foreigners Act and so on. I would like to know this from the Home Minister: Does it mean that the purpose of this Security Force will be mainly to discharge the functions of the border police in the sense that they will try to haul up illegal infiltrators, smugglers, dacoits, persons who lift cattle and forcibly seize paddy lands on the border or those who want to enter into Indian territory without passport? Does it mean that this force will be constituted only to perform these tasks? If so, I would say that the Indian Union contemplating a Central Force will fail not only to carry out the purpose, but there is apprehension that conflicts between the border States and the Centre will be created. But if it has been thought now, as I have already said that our borders are exposed to actual and potential enemies, if we feel the necessity of helping our Defence Forces by some sort of, I should not say police force, but auxiliary defence force performing a particular type of task, that should have been made clear. If our Government feel that the armed police force in Assam, Tripura, West Bengal, Jammu and Kashmir, Punjab or Gujarat or Rajasthan are not capable of dealing with certain other types of offences to which I have already referred, we expect that that should be mentioned as the main object of constituting this force. That means the types of offensive activities which we could expect from across the border as confirmed by our experience at the time of the Operation Gibralter from 'Azad' Kashmir. That means that some type of guerilla forces are now being organised in Pakistan which, we all know, attacked India even in 1965.

It is also known more, I think to our Home Ministry and Defence Ministry that in East Pakistan they are organizing *Ansars Mujahids* the East Pakistan Rifles and various types of para-militia with the help of Chi-

[Shri Samar Guha]

nese experts. Their purpose in constituting this para-militia is not merely to protect the border of East Pakistan from smugglers, illegal trespassers or infiltrators, but something else. At the time of hostilities, as you know these forces will create certain troubles because our Eastern border is nearly 2,300 miles. In the Western sector it is more, nearly 2,400 miles. We have also a northern border. Our defence policy has been chalked out on the basic presumption that in the eventuality of a future hostility India should expect a thrust from not only one side but simultaneously from three sides and in a synchronised way. It is also a known fact that the enemies, potential and actual, with whom we have to fight will depend to a very large extent on this para militia,—the guerilla type of army that they are training. Therefore, if the Home Minister feels that with a view to help and strengthen the hands of our defence forces we should build up a new type of defence force, call it para militia, call it security force, we should have a clear understanding in our mind that it will not be a mere duplication of the armed police force but that it will be a force having a special task, a special objective, to fulfil. Only if we keep this in mind the process of recruitment of these forces, the project of giving them training, the equipment that will be necessary for them and the specialised patriotic ideological training, I should say will be different.

Therefore, I say that though this Bill mentions about many other things, it does not mention what will be the actual status of this force, what will be the actual basic task that this force will have to perform. That is mentioned in only one sentence and again in the Miscellaneous Chapter in a confused way. Is it only to deal with infiltrators, smugglers, cattle-lifters or dacoits, or is it also to defend our border against probable guerilla warfare from the other side?

SHRI Y. B. CHAVAN: When it is said that it is meant for the security of the border, what does it mean?

SHRI SAMAR GUHA: That has to be explained.

SHRI Y. B. CHAVAN: The Bill says things precisely and accurately. I was amused to listen to his remarks. Clause 4 (1) says that there shall be an armed force of the Union called Border Security Force for ensuring the security of the borders of India. What further precise definition can be given? You can give a two-hour lecture, but the Act is supposed to be precise. I hope the hon. member understands it.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Why should it be sent outside India?

SHRI Y. B. CHAVAN: You raised that question and I was waiting for the time of my reply. In the course of hot pursuit, suppose he has to cross the border? Do you want it to be illegal? These are things which one has to understand.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Is it only for that much?

SHRI Y. B. CHAVAN: Only for that much.... (*Interruptions*) I do not want to go into all the minute details.

SHRI SAMAR GUHA: The hon. Minister explained the position and I am happy. If the purpose is not to be more explicit, it is quite all right. If he has to defend the border as the Home Minister says, the first task is to build up a different type of armed force. That means that they will have to be equipped differently, with that type of weapons which may be needed in hot pursuit also. A special type of training should be given. Recruitment should be more or less from the people who know the border areas and know the local situation also and have the traditional fighting

spirit. I was then not a Member of the House. But I cried hoarse that it would be wrong to disperse the Namasudra community, a brilliant fighting people coming from East Pakistan and of whom the potential enemy on the other side are mortally afraid, and send them to Nainital, some to Mana camp and some to Dandakaranya. I shall again request you to recruit them and put them in the border areas in West Bengal, Tripura and other places.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member's time is up.

SHRI SAMAR GUHA: I am talking sense.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Every Member is supposed to talk sense here. I have given him fifteen minutes. Please conclude in two minutes.

SHRI SAMAR GUHA: There are then the Chakmas. If they are settled in the Assam border and the Tripura border, instead of being dispersed in the interior of Assam and other places, the Nagas and the Mizos would not be able to cross into East Pakistan. Therefore, there should be recruitment from Chakmas for this force and they should be settled in the Tripura and Assam border. Thirdly, the Santhals had been squeezed out of East Pakistan and they are also martial people. All these people will provide good elements for this force. They should be given training in the handling of equipment and also training in ideology, I mean patriotic training. There is a lot of difference between the guerilla type of war and the other war, and also between the guerilla army and the ordinary army. Unless the guerilla type of army is inspired and motivated by certain nationalistic ideology and patriotic objective, they could not function.

For that reason I would request the Home Minister to keep in view the question whether a certain kind of special ideological training—ideological not in the political or partisan sense but patriotic and nationalistic ideological training—is necessary so as to equip them not only physically but mentally also.

Sir, I will conclude by saying that this has been drafted hastily. Not more than two weeks should be taken by a Select Committee to consider this. I have experience of the working of Joint Committees. Everyone will agree with the urgency of having this Bill passed. Yet I request that a thorough scrutiny should be made of the provisions of this Bill and, therefore, it should be referred to a Joint Committee at least for two weeks.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): Mr. Chairman, Sir, they say everything looks yellow to the jaundiced eye. A patient suffering from this dangerous ailment may yet hope to get cured by expert medical treatment in proper time. But a person who falls a victim to political jaundice runs the risk of being classified in history as a political maniac. Sir, without meaning any disrespect to any section of this august House, I cannot but conclude that a few friends here have almost touched that point. Otherwise, it is difficult for me to comprehend why so much of criticism should be levelled by some hon. Members against the Bill which in its present form is quite harmless and is expected to fulfil the national task of ensuring the security of borders of India and matters connected therewith having laid down provisions for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union.

Sir, I would like to draw your pointed attention to an alarming aspect of our parliamentary functioning. We have been facing an epidemic of over-legislation which is bound to make our Law Ministry and the Legislative Department sick and suffering. How can our Law Ministry and Legislative Department be expected to function normally and efficiently if every third day a Bill has to be cooked up to meet a particular event in the country and events are too

[Shri Krishna Kumar Chatterji]

plentiful nowadays? I do not, therefore hesitate to congratulate the Law Ministry and the Legislative Department for coping so wonderfully well with such an abnormal if not absurd demand on its intelligent and efficient functioning.

Sir, one hon. Member of this House was pointing out to me that the only demonstration of intelligence in a Member is his ability to bring forward amendments to a particular Bill and he was lamenting that we on this side seldom exercise such intelligence. I humbly submit that it does not require much of brain to understand the pattern and the contents of any Bill once you get accustomed with the Bills that are presented before the House.

श्री झारखण्ड राय : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई सदस्य लिखा हुआ भाषण पढ़ सकता है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What the hon. Member says is a good commentary on how we legislate here, but I would request him to come to the Bill that is before the House.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: I have gone through the many amendments tabled by hon. Members in this House and it is not difficult for me to find the motivation behind them. In a multi-party system which has unfortunately developed in our parliamentary life legislative manoeuvrings are there for political reasons. Sir, on this side of the House it will be intelligent participation if we can raise a purposeful debate by trying to rebut and resist the political implications and complications sought to be introduced by the opposition. Sir, it is for you to see that this Parliament is not reduced to a debating society of high school standard. Let us have less of such Bills and more of purposeful functioning on national questions.

The idea of Select Committees does not attract me either, although it may lead to financial advantages to me if I find a place in such a committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now you are a well-experienced and senior member of this House. You are almost reading from a manuscript for which objection has been taken. You can refer to some points but not read a speech.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH (Parbhani): He is only referring to the notes.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: Very often such committees are unnecessary and the huge losses which such committees infilict on our impoverished public exchequer is, to my mind, not conducive to our national interest.

I entertain the highest respect for our Home Minister, whose astuteness, forthright honesty and bold patriotism have earned for him overwhelming support from all quarters even in the discharge of an irritant though noble duty. But it is difficult for me to appreciate the need for such a voluminous Bill when the provisions of the existing Army Act could have been suitably amended to bring the Border Security Force within its ambit.

In the labyrinth of our legislative measures of this type sometimes vital needs of the community get ignored and sacrificed in a dangerous way. We have become much too sophisticated in legal functioning so much so that the entire human population in this unfortunate country of ours is a slave unto the law. Sir, I hope you will agree with me that a legal system which enslaves the community is a menace to any human society and is certainly a hindrance to human progress.

Therefore, our border security problems should not be treated in a manner as is being treated now even by a

strong Home Minister like Shri Chavan who has only recently earned from a grateful nation the title of Sardar like Sardar Patel revered memory.

It is my considered view as one belonging to a strategic border State that the border security duties should be handed over to the army because of the perilous nature of our long borders in the face of the belligerent and bellicose attitude of our nearest neighbour Pakistan and our greedy enemy, Red China, even at this date continuing wrongful and aggressive occupation and possession of large chunks of our motherland.

The recent penetration of Soviet Russia in Pakistan with military supplies may not, by itself, endanger our national security as this diplomatic role and posture may in the long run check considerably the unholy flirtation between Red China and Pakistan thus preventing the possibility of another war against us. But, even then we can ignore such an event as a nation only at our own peril Tightening the border security arrangements is a must with us and I congratulate the Home Minister for being alert and vigilant and for bringing the present Bill before the House for enactment.

The large-scale smuggling of gold, silver and important luxury articles and even articles of every-day use through our long border areas has assumed such an alarming proportion that it would be a national folly to be complacent in the matter of dealing with our borders in a lop-sided manner. We are told that in the West Bengal border there is influx of people from East Pakistan. On the 19th of July it was reported in the newspapers that two of our border force people were killed and others were injured. It seems that certain East Pakistani people were coming to our land and trying to cultivate our land. When the border security force tried to resist that, since they were provided with only very scanty arms and ammunitions, they were killed in action. This should also be borne in mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member should conclude now.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: I shall conclude in two minutes' time.

In the border areas of West Bengal there are possibilities of internal subversion also. It is recent history that the Naxalite elements of the Communist Party are creating havoc in West Bengal and the question of internal subversion is there. Therefore the Border Security Force has a double function to perform to secure our borders against external invasion and to see that internal subversion is not there. For this purpose we have to equip our Border Security Force with arms and ammunition and give them amenities and emoluments commensurate with the risk and the hard task that they take up. It is very essential for West Bengal because we have to face a very serious situation there. Because of these anti-social and political elements who are trying to subvert our national security, the Border Security Force has got a special performance to make. I should think that there should have been a clause saying that the border police would be equipped with such-and-such border equipment so as to make it being called the border police force. This is very essential and I would appeal to the hon. Home Minister to see to it.

With this I commend the Bill for the unanimous acceptance of the House.

श्री अब्दुल गनी डार (गड़गांव) : मझे खुशी है कि होम मिनिस्टर साहब इस बिल को हाउस के सामने लाए हैं। जब श्री समर गुह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि

[श्री अब्दुल गनी दार]

यह बिल जल्दबाजी में लाया गया और तैयार किया गया है। इस पर शायद चह्वाण साहब नाराज हो गए थे। लेकिन आप देखें कि इस बिल में शेमफुली, कावर्डली वगैरह जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है। ये अल्फाज ऐसे हैं जो कि मैंने आज तक अपने कानों से अपनी ही फोर्स के बारे में नहीं सुने हैं। इस फोर्स के बारे में अभी हमारी बहन कह रही थीं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है और अपनी जान पर खेल कर भी देश की हिफाजत की है। मैं भी इस बात को मानता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे चह्वाण साहब को भी जो कि बहादुर शिवाजी की औलाद हैं, ऐसे अल्फाज का अपनी ही फोर्स के बारे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिये था।

14.58 hrs.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

एक तरफ तो हम उनकी तारीफ करते हैं लेकिन दूसरी तरफ भाई चह्वाण साहब चाहते हैं कि उन पर तरह तरह की पाबन्दियां लागू कर दी जायें। इसका साफ मतलब यह है कि उन्हें डर है कि हमारी बोर्डर आर्म्ड फोर्स में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो पालिटिक्स में दखल देते हैं या जो लेबर मूवमेंट या पेजेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अगर उन पर पाबन्दियां लगाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि कोई न कोई डर सरकार के मन में है और अगर डर है तो हमें रिक्रूटमेंट करते समय काफी सोच विचार से काम लेना होगा और देखना होगा कि हमारी फोर्स में ऐसे लोग न आ जाएं जो देश की हिफाजत के नाम पर अपने जाती अगराज को या अपने पालिटिक्स को तरजीह देना चाहते हों।

यह भी कहा गया कि हिन्दुस्तान में भी वे हिफाजत करें और आउटसाइड इंडिया भी करें। अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसा भी क्रूशल प्वाइंट आ जाता है जब कि देश की हिफाजत इस बात की मांग करती है कि वे आगे जायें। मैं समझता हूं कि अगर आप आउटसाइड इंडिया भी कहते हैं तो आपका जो मकसद है कि बोर्डर की उनको हिफाजत करनी है उसको शायद धक्का पहुंचाते हैं। बाहर जाने के लिए और लोग मौजूद हैं और वे जाते भी हैं। आम तौर पर आपने फौज को ही आउटसाइड इंडिया भेजा है। इस वास्ते मैं समझ नहीं पाया हूं कि इसको क्यों क्लीयर न कर दिया जाए।

एक बात मैं दुःख के साथ अर्ज करना चाहता हूं। हमारा पिछले चन्द सालों का तजुर्बा यह है कि बावजूद हमारी इंतहाई कोशिश के हम अपने बोर्डर्ज को महफूज नहीं कर पाए। घुसपैठिए आए और ऐसी हालत में आए जब कि हमारी बोर्डर पुलिस मौजूद थी। जब वहां पर हमारी फौज और स्टेट की पुलिस मौजूद थी, तो वे कैसे आ गए? अगर दो, चार, दस, बीस आये होते, तो हम समझते कि वे किसी न किसी साजिश से आ गये, लेकिन वे हजारों की तादाद में आए और श्रीनगर के एयरपोर्ट तक पहुंच गये। ये बाते श्री चह्वाण को चौकन्ना करने के लिए काफी हैं। अभी अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब के सिपाहियों ने आसाम में वाके नागा हिल्स और मिज़ो हिल्स में तरह तरह के हथियार पकड़े। जब हमारी बार्डर पुलिस वहां पर मौजूद थी, तो वे हथियार कैसे आ गये और कैसे वे लोग ट्रेनिंग के लिए चीन या पाकिस्तान गये? ये सब वाकयात इस बात का एहसास कराते हैं कि हमारी आर्गेनाइजेशन में कुछ न कुछ कमी है। इस कमी को कैसे दूर किया जाये और बाहर से घुसपैठियों और हथियारों को इस मुल्क में आने से रोका जाये, यह तो हकूमत और होम मिनिस्टर साहब का अपना काम है।

15 hrs.

श्री समर गुह ने अभी अभी कहा कि बार्डर पर उन आदमियों को रखा जाये,

जो वहां के तमाम दर्रों और गली-कूचों से वकिफ़ हों। यह तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर इस तरह किया जाये तो फौज कैसे जगह जगह जायेगी? मैं इस बात को नहीं मानता हूं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुल्क की तक्सीम अब्दुल गनी ने नहीं कराई और न ही करोड़ों मसलमानों ने कराई। कुछ लोगों ने अंग्रेज की मदद से यह आवाज उठाई और हमारे दोनों बड़े नेताओं ने, जिन पर हमें बड़ा मान है, गांधी जी की मर्जी के खिलाफ तक्सीमे-मुल्क को माना। लेकिन तक्सीम के बाद कैनेडा और यू० एस० ए० की तरह एक दोस्ताना माहौल में रहने के बजाय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैजिनो लाइन और सीगफीड लाइन की तरह किलाबन्दी करने की जरूरत महसूस हुई। यह ठीक है कि इसमें बुनियादी गलती पाकिस्तान की है, लेकिन अगर हम तक्सीमे-मुल्क की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालें, तो यह सही नहीं होगा।

बदकिस्मती से पिछले बीस साल का हमारा तजुर्बा यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद हम हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर पूरा भरोसा नहीं कर पाये, जो करोड़ों की तादाद में यहां बसते हैं। चाहे उनमें अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उसमान, किदवई और आजाद हों, लेकिन हम उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पाये। यहां तक कि डा० जाकिर हुसैन के बारे में भी, जब वह उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति होने के बाद भी, तरह तरह की बातें उड़ाई गईं। स्टेट्स की पुलिस में मुसलमानों को सर्व करने का मौका नहीं दिया गया। यह तो सैंटर की अपनी पुलिस है। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वह इस सिलसिले में मुसलमानों पर भरोसा करें। वे क्यों मौरिदे-इल्जाम ठहराये जायें? पिछले बीस सालों से फौज और पुलिस के दरवाजे उन पर बन्द हैं। (*Interruptions.*) मैं यह कहना चाहता हूं कि बार्डर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहिए। उसको डीमारेलाइज नहीं करना चाहिए। उसमें ऐसे आदमियों को लेना चाहिए, जो वफादार हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। हम इस वक्त बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स पर विचार कर रहे हैं। इस फोर्स में रिक्रूटमेंट के बारे में जो नियम बनाए जाने हैं, व अभी बनने हैं। इसलिए क्या यह उचित होगा कि हम कम्यूनल टर्म्ज में बात करें और इस तरह के सुझाव दें। मैं समझता हूं कि यह बिल के स्कोप और उद्देश्यों के विरुद्ध होगा और इस समय जो वातावरण है उसके लिए भी वह ठीक नहीं है।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं होम मिनिस्टर साहब से यह बात इसलिए अर्ज कर रहा था कि यह महकमा उनके तहत है, स्टेट्स के तहत नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि पुलिस का महकमा सेंटर के तहत हो। श्री मधोक तो प्रोफेसर हैं। मैं उनका अदना शागिर्द हूं। नियम तो होम मिनिस्टर साहब ने बनाने हैं, श्री मधोक या अब्दुल गनी दार ने नहीं बनाने हैं। वह इस फोर्स में उन तमाम लोगों को लें, जिन पर वह भरोसा करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मुसलमान हमलावर होते थे, उस वक्त हिन्दू राजाओं के तोपची मुसलमान हुआ करते थे। अच्छा होता कि श्री मधोक या श्री चव्हाण या श्रीमती इन्दिरा गांधी पाकिस्तान के फारेन मिनिस्टर, अर्शद हुसैन के इस इल्जाम का जवाब देते कि इस मुल्क में हजारों जगह मुसलमानों को कत्ल किया गया, लेकिन एक कातिल को भी सजा नहीं दी गई। यह कैसा देश है? मैं एक दोस्त, साथी और मेम्बर के नाते यह सुझाव दे रहा हूं कि हकूमत उन पर भरोसा करे और जिन लोगों पर उसको भरोसा है उनको इस फोर्स में काम करने का मौका दे। अब यह मौका उनको जरूर मिलना चाहिए।

[श्री अब्दुल गनी दार]

इस फ़ोर्स के लोगों के लिए जो सख्त और भद्दे शब्द इस्तेमाल किये जा रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसके बजाय यह कहा जा सकता है कि अगर किसी से गलती होगी तो उसको ऐसी सजा दी जायेगी। यह चव्हाण साहब के शायाने-शान नहीं है कि इस तरह के अल्फाज इस बिल में हों।

मैं आपका शुक्रया अदा करता हूं।

[شری عبد لغی ڈار (گوڑگاوں) : مجھے خوشی ہے کہ ہوم منسٹر صاحب س بل کو ہاوس کے سامنے لائے ہیں - جب شری سمرگوہا بول رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بل جلد-بازی میں لایا گیا اور تیار کیا گیا ہے- اس پر شاید چوان صاحب ناراض ہو گئے - لیکن آپ دیکھیں کہ اس بل میں شیمفلی - کاوڑڈلی وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے - یہ الفاظ ایسے ہیں جو کہ میں نے آج تک اپنے کانوں سے اپنی ہی فورس کے بارے میں نہیں سنے ہیں - اس فورس کے بارے میں ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھیں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اپنی جان پر کھیل کر بھی دیش کی حفاظت کی ہے - میں بھی اس بات کو مانتا ہوں - میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چوان صاحب کو بھی جو کہ بہادر شواجی کی اولاد ہیں - ایسے الفاظ کا اپنی ہی فورس کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہئے تھا -

ایک طرف تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن دوسری طرف بھائی چوان صاحب چاہتے ہیں کہ ان پر طرح طرح کی پابندیاں لاگو کر دی جائیں - اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اُنہیں ڈر ہے کہ ہماری بورڈر آرمڈ فورس میں کچھ ایسے لوگ گھس گئے ہیں جو پالیٹکس میں دخل دیتے ہیں یا جو لیبر موومنٹ یا پیزینٹ موومنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں - اگر ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ڈر سرکار کے من میں ہے اور اگر ڈر ہے تو میں رکروٹمنٹ کرتے سمے کافی سوچ وچار سے کام لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہماری فورس میں ایسے لوگ نہ آجائیں جو دیش کی حفاظت کے نام پر اپنے ذاتی اغراض کو یا اپنے پالیٹکس کو توجیح دینا چاہتے ہوں -

14.58 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair.*]

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں بھی وہ حفاظت کریں - اور آؤٹ سائڈ انڈیا بھی کریں - ابھی ابھی منتری مہودے نے کہا تھا کہ ایسا بھی کروشل پوائنٹ آ جاتا ہے جب کہ دیش کی حفاظت اس بات کی مانگ کرتی ہے کہ وہ آگے جائیں - میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آؤٹ سائڈ انڈیا بھی کہتے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے کہ بورڈر کی ان کو

کے لئے چین یا پاکستان گئے - یہ سب واقعات اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں کچھ نہ کچھ کمی ہے- اس کمی کو کیسے دور کیا جائے اور باہر سے گھسپیٹھیوں اور ہتھیاروں کو اس ملک میں آنے سے روکا جائے - یہ تو حکومت اور ہوم منسٹر صاحب کا اپنا کام ہے -

سری سمر گوہا نے ابھی ابھی کہا کہ بارڈر پر ان آدمیوں کو رکھا جائے - جو وہاں کے تمام دروں اور گلی کوچوں سے واقف ہوں - یہ تو بڑا مشکل کام ہے - اگر اس طرح کیا جائے - تو فوج کیسے جگہ جگہ جائیگی- میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں -

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی تقسیم عبدالغفار خاں نے نہیں کرائی اور نہ ہی کروڑوں مسلمانوں نے کرائی - کچھ لوگوں نے انگریز کی مدد سے یہ آواز اٹھائی اور ہمارے درمیان بڑے نیتاؤں نے - جن پر ہمیں بڑا مان ہے - گاندھی جی کی مرضی کے خلاف تقسیم ملک کو مانا - لیکن تقسیم کے بعد کینیڈا اور یو - ایس - اے - کی طرح ایک دوستانہ ماحول میں رہنے کے بجائے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میکموہن لائن اور سیگفریڈ لائن کی طرح قلعہ بندی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی - یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بنیادی غلطی پاکستان حفاظت کرنی ہے اس کو شائد دھکہ آپ پہنچاتے ہیں - باہر جانے کے لئے اور لوگ موجود ہیں اور وہ جاتے بھی ہیں - عام طور پر آپ نے فوج تو ہی بھیجا ہے آؤٹ سائڈ انڈیا - اس واسطے میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ اس کو کیوں کلیر نہ کر دیا جائے -

ایک بات میں دکھ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں - ہمارا پچھلے چند سالوں کا تجربہ یہ ہے کہ باوجود ہماری انتہائی کوشش کے ہم اپنے بورڈرز کو محفوظ نہیں کر پائے گھس پیٹھئے آئے اور ایسی حالت میں آئے جب کہ ہماری بورڈر پولیس موجود تھی - جب وہاں پر ہماری فوج اور سنٹیٹ کی پولیس موجود تھی - تو وہ کیسے آگئے - اگر دو - چار - دس - بیس آئے ہوتے - تو ہم سمجھتے کہ وہ کسی نہ کسی سازش سے آ گئے - لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے اور سریلنکر کے ایر پورٹ تک پہنچ گئے - یہ باتیں شری چوہان کو چوکنا کرنے کے لئے کافی ہیں - ابھی ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب کے سپاہیوں نے آسام میں واقع ناگا ہلس اور میزو ہلس میں طرح طرح کے ہتھیار پکڑے - جب ہماری بارڈر پولیس وہاں پر موجود تھی - تو وہ ہتھیار کیسے آ گئے اور کیسے وہ لوگ ٹریننگ

[شری عبدالغنی ڈار]

کی ہے - لیکن اگر ہم تقسیم ملک کی ساری ذمہداری پاکستان پر ڈالیں - تو یہ صحیح نہیں ہوگا -

بدقسمتی سے پچھلے بیس سال کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر پورا بھروسہ نہیں کر پائے - جو کروڑوں کی تعداد میں یہاں بستے ہیں - چاہے ان میں عبدالحمید - برگیڈیر عثمان - قدوائی اور آزاد ہوں - لیکن ہم ان پر پورا بھروسہ نہیں کر پائے - یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں بھی - جب وہ آپ راشٹرپتی تھے اور راشٹرپتی ہونے کے بعد بھی - طرح طرح کی باتیں اٹھائی گئیں - سٹیٹس کی پولیس میں مسلمانوں کو سرو کرنے کا موقع نہیں دیا گیا - یہ تو سینٹر کی اپنی پولیس ہے - اس لئے میں ہوم منسٹر صاحب سے عرض کرونگا کہ وہ اس سلسلے میں مسلمانوں پر بھروسہ کریں - وہ کیوں موردالزام ٹھہرائے جائیں - پچھلے بیس سالوں میں تو فوج اور پولیس کے دروازے ان پر بند ہیں - (*Interruptions*) میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پولیس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہئے - اس کو ڈیماریلائز نہیں کرنا چاہئے - اس میں ایسے آدمیوں کو لینا چاہئے - جو وفادار ہیں -

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : आन ए पाइंट आफ़ आर्डर । हम इस वक्त बार्डर सिक्युरिटी फ़ोर्स पर विचार कर रहे हैं । इस फ़ोर्स में रीक्रूटमेंट के बारे में जो नियम बनाए जाने हैं, वे अभी बनने हैं । इस लिए क्या यह उचित होगा कि हम कम्यूनल टर्म्ज में बात करें और इस तरह के सुझाव दें ? मैं समझता हूं कि यह बिल के स्कोप और उद्देश्यों के विरुद्ध होगा और इस समय जो वातावरण है उसके लिए भी वह ठीक नहीं है ।

شری عبدالغنی ڈار : میں ہوم منسٹر صاحب سے یہ بات اس لئے عرض کر رہا تھا کہ یہ محکمہ ان کے تحت ہے - سٹیٹس کے تحت نہیں ہے - میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پولیس کا محکمہ سینٹر کے تحت ہو - شری مدھوک تو پروفیسر ہیں - میں ان کا ادنیٰ شاگرد ہوں - نیم تو ہوم منسٹر صاحب نے بنائے ہیں - شری مدھوک یا عبدالغنی ڈار نے نہیں بنائے ہیں - وہ اس فورس میں ان تمام لوگوں کو لیں - جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں - میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان حملہ آور ہوتے تھے - اس وقت ہندو راجاؤں کے توپچی مسلمان ہوا کرتے تھے - اچھا ہوتا کہ شری مدھوک یا شری جوشی یا شری متی اندرا گاندھی پاکستان کے فارین منسٹر - ارشد حسین - کے اس الزام جواب دیتے کہ اس ملک میں ہزاروں جگہ تو مسلمانوں کو قتل

کیا گیا - لیکن ایک قاتل کو بھی سزا نہیں دی گئی - یہ کیسا دیش ہے - میں ایک دوسرے - ساتھی اور ممبر کے ناطے یہ سجھاؤ دے رہا ہوں کہ حکومت ان پر بھروسہ کرے اور جن لوگوں پر اس کو بھروسہ ہے - ان کو اس فورس میں کام کرنے کا موقع دے - اب یہ موقع ان کو ضرور ملنا چاہئے -

اس فورس کے لوگوں کے لئے جو سخت اور بھدے شبد استعمال کئے جا رہے ہیں - وہ ٹھیک نہیں ہیں - اس کے بجائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہوگی - تو اس کو ایسی سزا دی جائیگی - یہ چوہان صاحب کے شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ اس بل میں ہوں -

میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad): Mr. Chairman, Sir, I welcome this Bill very heartily. So far, our borders have been, to a certain extent, neglected and security of the country is a paramount concern of us all.

Some suggestions have been made as to what sort of Force it should be. The Border Security Force, some hon. Members suggest, should be exactly like the Army with the same discipline, with the same provisions, with the same facilities, with the same arms and same officers. That may appear to be advantageous. But it is really not so because, if you have an Army simply clothed in police uniform, outside countries will consider it and take it as an Army. When you have an Army on such a long border, even if there is a thin line, there is no way to stop others from assuming that there is a regular Army in depth behind that line. Therefore, a suspicion will grow. So, ultimately, theoretically at least, it would mean one Army facing another Army all the time. That is not in the interest of the country nor its security. Those concepts of Maginot line are out of date. The Border Security Force, as has been stated in the Bill, has got some limited function. They are a Security Force. They are not there to defend from an organised attack. That is the function of an Army. Therefore, for this Force to be effective, it should be something more than the ordinary police but at the same time, it should be something less than the regular Army. It should be trained and recruited very carefully. At the same time, it should be mobile. On the border, they must have facilities of moving by jeeps or any other means and also of communication with the hinterland. If these are provided, then it will perform a useful function.

It has been suggested by some Members that these forces are having collusion with their counterparts in Pakistan on the border and they are allowing smuggling to go on and they are also sharing in the commission. I do not believe this. All this depends upon how they function and how we implement the provisions that are already there. However strict a punishment may have been provided for, it would not be effective unless it is implemented in a fair and just manner.

I have no doubt in my mind whatsoever that the people and the youth of India today are hungering for moral action. They want opportunities to work in such a way that some ideal is served. It does not matter whether it is an ordinary worker or student or a clerk, but we are not providing that opportunity or that atmosphere of idealism. If this force could be charged with this responsibility and told 'The country of India is depending on you,

[Shri Bakar Ali Mirza]

and you are to secure the borders of India', I think Government will get a very favourable response.

Now, I would say something about some political things that have been mentioned, especially by my hon. friends Shri Balraj Madhok and Shri Himatsingka. Shri Balraj Madhok had just objected to what my hon. friend Shri Abdul Ghani Dar had said, perhaps, in his view, rightly. But it was he who had suggested that there should be a ten-mile gap between the two frontiers . . .

SHRI BALRAJ MADHOK: I want to correct my hon. friend. I had not suggested it myself. I only said that the plans and the schemes were there but they had not been implemented. The plans and schemes are already there.

SHRI BAKAR ALI MIRZA I had given him the credit of suggesting them. I think he at least approves of them. The other suggestion is that the refugees are to be settled on the borders . . .

SHRI BALRAJ MADHOK: Ex-soldiers.

SHRI BAKAR ALI MIRZA Ex-soldiers or whatever they be, they are refugees.

SHRI BALRAJ MADHOK: I said 'ex-soldiers'. How can they be refugees?

SHRI BAKAR ALI MIRZA Ex-soldiers are also refugees.

SHRI BALRAJ MADHOK: Some may be refugees, but not all ex-soldiers would be refugees.

SHRI BAKAR ALI MIRZA: Shri Himatsingka had used those words. And it had been suggested more than once. Perhaps my hon. friend keeps himself in guard all the time because be is a professor. Anyhow, this suggestion has been made in this House, but I think that it is very unfortunate. What does it imply? It implies that we in this country consider people coming from some other country to our country as more loyal than the people of this country, however great and noble they may be. Why should refugees or ex-soldiers or anybody else become more important than a man, a dacoit or even a person with no character or a person like myself? I consider that it is a reflection on the whole country. I maintain that we cannot build a real protection for this country unless we not only think of outside the border but also think inside the border.

Then, a suggestion had been made that the Namashudras should be settled there. If the persons are selected from among the people of India I have no objection. But if we are to select from among the refugees than it is possible that spies may be infiltrating. Therefore, I would submit that the so-called exsoldiers need not necessarily be settled there. Does Shri Balraj Madhok maintain that the Sanatan Dharmists from Pakistan are not functioning in a cell as spies? Therefore, I submit that this whole concept is wrong.

Then, we are thinking in terms of Pakistan being and continuing to be a theocratic State all the time. Suppose there is a change tomorrow and there is a communist State in East Ptkistan, what will be the reaction of the people whom we have settled on the border? These refugees are really a risk to be taken in that way. This whole concept is another version of extra- territorial loyalty about which Shri Balraj Madhok complains so much.

The trouble is that after Partition, in this country and also in Pakistan, we are working with double citizenhisp. A person is a citizen of India or Pakistan because he is born there. Still, he is a citizen of another country because he belongs to a particular community. It is this kind of concept which is really doing a great deal of damage. If we are to think of the country, then we should take the coun-

try as one. I have said this before and I say it again that the first thing to do is to close the border for the people from Pakistan on the one side and the people from India on the other. If I happen to be or prove to be a traitor or something of that kind, then you may hang me, try me and hang me, but do not just shove me out and say that another country is waiting to welcome me. This is not the way we can maintain the security of India.

In conclusion, I say that I welcome this Bill. I regret very much the political and communal undertones that have been injected into the debate. I would not have replied in that way but for the fact that I had been provoked by the remarks made by some of my friends here. This concept of Maginot line, Berlin wall and all that will not succeed. We may have a Berlin wall, but if there is economic advantage, the people will cross over, no matter what we do.

I welcome this Bill and I hope that the hon. Minister will keep in mind whatever I have said.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): A few minutes ago, when I suggested that the Bill might go to the Select Committee, the hon. Minister very vehemently said 'No'.

AN HON. MEMBER: He did not say it.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Very well, it was another Minister who is not here just now who had said that, namely Dr. Ram Subhag Singh.

Why do I want it to go before a Select Committee? I do so because this is a very important Bill and a very urgent Bill. When we say that it is an urgent Bill you may ask why it should go to the Select Committee? I say that it should go before the Select Committee in order to make this Bill as good as possible. But the hon. Minister says that it is urgent, and the urgency is reflected in the drafting of this Bill. The wording shows any amount of urgency, that is to say, absolutely hasty drafting.

Words are not used in the ordinary sense in which they are understood by us. Take the word, for example, 'suspension'. The phrase is in the marginal note 'computation of the period of suspension' in clause 133. Do not look into what is written in the body of the clause, but look at the marginal note. We shall say that it is computation of the period of suspension, the word 'suspension' being understood in the ordinary way. But the meaning in the Bill is:

> "Any period during which the sentence is under suspension shall be reckoned . . .

Nobody understands the word 'suspension' in that sense. Apparently, this is some archaic language borrowed from some archaic legislation.

Now, I shall give you another example of archaic usage in another place. The word 'discover' has been used. But in what sense? It has been used in the sense of 'inform'. The wording in the clause is:

> "having come by the knowledge of any such correspondence or communication, wilfully omits to discover it immediately to his Commandant or other superior officer.

This is not even eighteenth century language but it is seventeenth country language. It is taken over from the Army and then transferred to the border security force. It simply means in modern language 'inform'. Why should we use such archaic language? I can give you any number of such examples.

Then, we have the phrase 'grave reason to believe'. Normally we say 'If there is strong reason to believe', but here we find the words in

[Shri Tenneti Viswanatham]

clause 74 'grave reason to believe'. I am pointing these out not as howlers but merely to show that the drafting has not been done properly. This is a Bill to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India. Nothing would have been lost if in the 'Statement of Objects and Reasons' they had mentioned this; there they have simply mentioned 'Indo-Pakistan border'. That simply shows that they were in an absolute hurry; the Minister was saying 'urgent' and the draftsmen were in an absolute hurry and, therefore, there was no co-ordination between the title of the Bill and the 'Statement of Objects and Reasons'. Perhaps, if it goes to the Select Committee, not only these but in matters of substance we might be able to find many points on which there may be some inner contradictions.

As others have said, I also say emphatically that I welcome this Bill, If I am pointing out these defects of language, it is only to show that it is better to give a little more thought to the language. Now what have they done? What is the Act after all? The Act is an Act of punishment. There is only one chapter which is really the substance and that is Chapter II. In Chapter II, Clause 4, which authorises the Government to constitute the force, in sub-clause (2) it is said:

> 'Subject to the provisions of this Act, the Force shall be constituted in such manner as may be prescribed and the conditions of service of the members of the Force shall be such as may be prescribed."

In three lines, two 'manners' are to be "prescribed". Have the Government got any picture of this as to what they are going to prescribe? If they have some guidelines, why do they not take us into confidence? Everything is left to the manner of prescription. The constitution of the Force, the goverance of the Force, the command of the Force, the discipline of the Force, the emoluments of persons attached to the Force, the recruitment of other members to the Force, the rank, the precedence, powers, authority of officers—all are left to the rule-makers. How, in the name of legislative honesty, can we call it an Act if every thing is left to prescription by the rule-makers? There may be certain things which are certainly matters of detail and cannot be given in main section, but everything cannot be left to the prescription of rule-makers. If the Bill is referred to the Select Committee, we can see the substance of it. The substance must be given in the Act. The constitution of the Force and the command of the Force are also left to the rule-makers. Except a single honest sentence, namely, 'There shall be an armed force of the Union called the Border Security Force for ensuring the security of the borders of India', the rest is left to the rule-makers. In that case, so much need not have been printed; it could have been said, "Subject to such conditions and such rules that may be prescribed by the Government, the Government shall constitute and administer Border Security Foce". This is in fact the Bill.

Our friends have asked, what is the co-ordination between the army and this Border Force. I think, all countries have this Border Security Force. This morning I was hearing from the Radio that Czechoslovakia has got a border security guard and they are trying to defend the border against somebody who is coming from the east and the north. But what is the relation between the army and this force? Everybody is worried about it. This is really a matter of substance. It cannot be left merely to rule-making powers. I agree with so many other friends that this border

security force should not be a mere police force; it should be a real force, if necessary, a striking force. Before the army comes in, if the hordes and the Huns from the north, east or west intrude into our territory, this force cannot go on waiting. It must have some striking power. From what we saw in the exhibition yesterday, it is meant to have some striking power. But let it have a decent striking power, a good striking power. Otherwise, it will be a liability. That is why members have suggested that the men in the Force must be made to feel that they are as important as the army, although they will be functioning under the Home Minister while the army will be functioning under the Defence Minister. They must have that sense of honour and pride that they are there also to defend the border when it comes to that, by all means available.

I shall just narrate to the Home Minister what happened recently. Certain members of the SAP belonging to a Southern State—Special Armed Police—in Nagaland were returning on leave. They were suffering from a sense of frustration. They said 'We do the same work as the army, but we are not equipped, we are expected to do all that the army does; we have got all the disadvantages which the army has, but we have none of their privileges. Not only that, we are treated with a subordinate status'. They felt a sense of frustration at the border. They should not have that sense of frustration or inferiority, because that will affect the morale and efficiency of the force—I need not dilate upon that. That is the reason why members from all sides were saying that they must be given a place of honour along with the army units.

There is another thing. These are troublous times. Only the other day we were discussing the question of Soviet Russia's supply of arms to Pakistan. That is why now there is a sense of awareness. I congratulate Government on that, that this sense of awareness has dawned upon them. Till now we had some sort of border police. But with all that, it was possible for 2,000, 3,000 and 4,000 Nagas to go to China, get arms and coolly return, have underground confabulations and also have interviews with the Government of India. It is a peculiar system under which our borders have been guarded by the border security force hitherto. But hereafter it must be totally different, not only on the western side but also on the eastern side.

There is no doubt that this force will have to be divided into two sections, one which can tackle problems arising on the international borders of Rajputana, Gujarat and so on, and the other which must have first class training to guard the hilly border areas. Only yesterday the Captain of our Hockey Team was telling us that we have got to play our match at an altitude of 7,000 feet and we cannot maintain our international reputation and our first place in international championships unless we have special training for this purpose. Therefore, I hope arrangements will be made to divide the force into these two sections and special mountain training given, if not to the entire force, at least to that part of it which is to guard the hilly and mountainous border areas on the north and east.

So I repeat my appeal. Let this border security force be a real force. Let them have a sense of pride that they are doing their best to safeguard the borders of this country.

It is true that these people's functions are strictly defined under the instructions to be given by the Home Ministry, but when they are in the same place with the army, let them not be made to feel that they are in any way inferior in striking power to the army.

[Shri Tenneti Viswanatham]

In the matter of recruitment I believe you will follow the strictest scrutiny and screening before you take persons to this force.

Once again I suggest that for improving language and drafting if you go to the Select Committee, you will be doing the right thing.

श्री हेम राज (कांगड़ा): सभापति महोदय, मैं चव्हाण साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बिल सदन के सामने पेश किया । आज यह कहा जा रहा है कि यह बिल बहुत देर से आया । इससे पहले पंजाब की अपनी आर्म्ड पुलिस, राजस्थान की अपनी आर्म्ड कांस्टेबलरी, गुजरात की अपनी पुलिस और हिमाचल वालों की अपनी पुलिस थी । हर एक जगह की अलग अलग पुलिस अपना काम करती थी लेकिन हर एक स्टेट की यह मांग थी कि वे जो खर्चा बार्डर सिक्योरिटी पर करते हैं वह खर्चा सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, स्टेट के जिम्मे वह खर्चा नहीं पड़ना चाहिए । पहली मर्तबा, सन् 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया उस वक्त सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि बार्डर सिक्योरिटी को खुद सेन्टर को ही ले लेना चाहिए । इस लिहाज से मैं समझता हूं चव्हाण साहब बधाई के मुस्तहक हैं कि उन्होंने इस काम को सर अन्जाम दिया ।

अब मैं उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं । उन्होंने जो जिक्र किया है वह इन्डो पाकिस्तान बार्डर का जिक्र किया है उसमें गुजरात और राजस्थान भी आ जाता है । मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की पुलिस बैठी है और उसमें जो ऊपर का हिस्सा है, हिमाचल के साथ वहां इन्डो टिब्बेटन पुलिस है । उसी तरह से कश्मीर का हिस्सा है जहां कश्मीर बार्डर स्काउट्स हैं । मेरा निवेदन यह है कि जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की पुलिस है वह सारी ही इसमें समावेश हो जानी चाहिये ताकि मुख्तलिफ किस्म की जो पुलिस है, उनके जो जुदा जुदा रूल्स हैं, जुदा जुदा सर्विस कन्डीशन्स हैं, वह समाप्त हो जाएं । जिन दिनों लाहौल स्पिती मेरी कांस्टीटुएन्सी थी और वहां मुझे जाने का मौका मिला तो वहां यह भावना काम कर रही थी, उन दिनों वहां पर थोड़ा शक था कि हमारे साथ जो सुलूक होता है वह फौज से जुदा होता है । इससे एक दूसरे में नफरत की भावना पैदा हो जाती है । इसलिए मैं समझता हूं कि जहां आपकी फौजें बार्डर एरियाज में काम करती हैं और वहां पुलिस भी काम करती है तो वहां पर उन दोनों की सर्विस कन्डीशन्स में बहुत ज्यादा भेद नहीं होना चाहिए। जो उनमें फर्क है वह एक दूसरे में नफरत की भावना पैदा न करे, इस तरह की सर्विस कन्डीशन्स आपको रखनी चाहिए ।

इसके साथ ही मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं । हमारे बहुत सारे नौजवान जो कि इमरजेंसी कमीशन्ड आफिसर्स हैं जिन को फौ मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे बहुत सारे नौजवान बार्डर सिक्योरिटी फोरसेज में लिए जा सकते हैं । जो आठ हजार इमरजेंसी कमीशन्ड आफिसर्स हैं उनमें से बहुत कम, पचास परसेंट से भी कम, अभी तक एबजार्ब किए जा सके हैं । मैं समझता हूं कि जो ऐसे आफिसर्स हैं वे इसमें बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं और उनको इसमें ले लिया जाना चाहिए ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फौज के जो सिपाही हैं उनको सात साल की सर्विस के बाद और आफिसर्स को 45 साल की उम्र में वापिस भेज दिया जाता है । एक सिपाही 30–35 साल की उम्र में घर वापिस आकर बैठ जाता है और उसके लिए कोई रोजगार नहीं होता है । तो मेरा कहना है कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में उन लोगों

को भी लिया जाये जो कि सिखाये हुए हैं और अच्छी तरह से काम भी कर सकते हैं।

इसके साथ मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं। हमारा जो ईस्टर्न बार्डर है उसमें भी और बाकी जो बार्डर्स हैं जैसे कश्मीर का बार्डर उसमें भी, अभी जैसा मेरे भाई अब्दुलगनी जी ने कहा कि विश्वास नहीं किया जाता है लेकिन में समझता हूं विश्वास तो है, चाहे वह माइनारिटी कम्युनिटी हो या मेजारिटी कम्युनिटी हो क्योंकि कश्मीर का बार्डर जो है वहां पर उससे पहले इतला देने वाले माइनारिटी कम्युनिटी के लोग ही थे कि यहां पर पाकिस्तानी हमलावर आ गए हैं। इसलिए अविश्वास का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। अगर वहां पर माइनारिटी कम्युनिटी के हमारे भाई उस बात की इत्तला न देते तो हमारी फौजों को उसका पता ही न लग पाता, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को उसका पता ही नही लग पाता। इस लिए मैं समझता हूं इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। हर आदमी जोकि हिन्दुस्तान की सलामती में विश्वास रखता है, उसको हमें इस फोर्स में लेना चाहिए और किसी पर अविश्वास करने का जरूरत नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि जो हमारे बार्डर एरियाज हैं वहां पर कुछ एलिमेन्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जोकि हमारी फोर्स में आ जायें और हमारी सलामती को खतरा पहुंचा दें। मेरे से पहले भी कुछ भाईयों ने इस बात को कहा है। मैं समझता हूं रूल्स में इस बात को रखा जायेगा कि जिनकी भावना दूसरी तरफ जाती हो उनको किसी भी सूरत में इस फोर्स में नहीं रखा जायेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जहां जहां हमारी पंजाब आर्म्ड पुलिस थी वहां पर बार्डर एरियाज में पब्लिक को भी ट्रेनिंग देनी शुरू हुई थी, गुरिल्ला वार की तरह से या शूटिंग के लिये ताकि वहां के लोग बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मौके पर मदद कर सकें लेकिन वह जो ट्रेनिंग है वह सारी उम्र में एक मर्तबा 15 दिनों के लिए दी जाती है और फिर उसको बन्द कर देते हैं। बार्डर के लोग चाहते हैं कि उनको आए साल 15 दिन की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि जिस समय भी कोई ऐसी बात हो वे फोर्स के साथ मिलकर एनिमी का मुकाबला कर सकें।

इसके साथ एक बात की जरूरत और है। यह जरूरी है कि बाकी पुलिस में और इसमें कोआर्डिनेशन हो क्योंकि बाज मर्तबा कोआर्डिनेशन न होने की वजह से आपस में रंजिश पैदा हो जाती है। जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, स्टेट की पुलिस है और सैन्ट्रल रिजर्व फोर्स है, हमने अक्सर देखा है कि इनमें आपस में डिफरेंस पैदा हो जाता है इसलिए इनमें आपस में कोआर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है।

आप जो यह बिल लाए हैं वह बहुत बा-मौके लाए हैं और इसको जरूर पास हो जाना चाहिये। जैसा कि श्री विश्वनाथन जी ने कहा कि इस को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यह मान सकते हैं कि इसमें कहीं पर कोई अलफाज या मामूली फेर-बदल की जरूरत हो लेकिन उसको तो इस वक्त भी अमेन्डमेन्ट के जरिये से ठीक किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई सेन्स ही बदलना जरूरी हो इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि यहीं पर इसको पास कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, इस विधेयक को हमें हिन्दुस्तान के सियासी हालात के पसे मंजर में देखना चाहिए। हमारे देश का संविधान संघीय है। इस विधयक को लाने का टाइम क्या है ? जब 67 के आम

[श्री झारखण्डे राय]

चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता का एकाधिकार हिन्दुस्तान के दो-तिहाई भाग से टूट गया उस समय इस विधेयक को लाया गया है। संघीय व्यवस्था को कायम रखते हुए भी हमारे होम मिनिस्टर साहब ताकत का केन्द्रीयकरण करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक लाया गया है। वहां इस का कोई औचित्य नहीं है। जब हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेनाएं हैं तो फिर यह बौरडर सिक्योरिटी फोर्स की क्या जरूरत है? जब अलग अलग राज्यों में पी० ए० सी० मौजूद है जोकि इस तरह के काम करती है और उस से यह काम कराया जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० नागालैंड में काम कर रही है, बहुत सी सीमाओं पर की ड्यूटियां उन्हें दी गई हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, उस की प्रशंसा केन्द्रीय सरकार ने भी की और जहां जहां पर यह उत्तर प्रदेश की पी०ए० सी० गई वहां वहां की सरकारों ने उस की प्रशंसा की है तो फिर यह डुप्लीकेशन की क्या जरूरत है। गृह-मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रदेशों में कई तरह की फोर्सेज तैयार की जा रही हैं और उनका एमल्गमेशन करके एक बना कर भी वह काम कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का ही आप नमूना ले लें। वहां पर पी० ए० सी० भी है, सिविल पुलिस भी है, पी० आर० डी० भी है और साथ ही साथ होमगार्ड भी है। अब होमगार्ड और पी० आर० डी० का एक तरह का काम है। इस तरह के डुप्लीकेशन के होने से खर्चा बढ़ता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के या शक्तियों के बढ़ाने से एक तो उन में आपस की प्रतिद्वंदिता पैदा होती है और एक समन्वय के साथ इन में काम नहीं होता है। इस लिए यह कहना कि शक्ति को केन्द्रित करने के लिए यह बौरडर सिक्योरिटी फोर्स की रचना की जा रही है मैं चाहूंगा कि गृह-मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि पी० ए० सी० जो सूबों में बनी हुई है, उस का और इस का क्या सम्बन्ध होगा। क्या इस की सम्भावना नहीं है कि इन में एक द्वैतवाद डुएलिज्म पैदा होगा और इससे कहीं एक उनमें टकराव भी पैदा हो सकता है? अब आज वह स्थिति नहीं रही है जोकि आज तक कांग्रेस पार्टी की इस देश में रही है। यह सम्भव है कि केन्द्र में यूनाइटेड सरकार बने और किसी सूबे में कांग्रेस सरकार रहे। यह भी सम्भव है जैसा कि आज है कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार है और दूसरे बहुत से सूबों में मिली जुली सरकारें बनीं और एक प्रदेश ऐसा भी है जहां एक पार्टी की सरकार है। जब आज ऐसी नई स्थिति पैदा हो रही है तब मेरी समझ में इस बौरडर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना करने से एक द्वैतवाद जरूर पैदा होगा शक्ति का, जिस से देश को नुकसान होने की सम्भावना है।

पुलिस स्टेट सब्जैक्ट है इसमें कोई दो राय हम में से किसी की नहीं हैं। तो क्या उसको बाईपास करने के लिए यह बनाया गया है? आखिरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर केन्द्र के हाथ में सत्ता लेने से प्रदेशों की आर्म्ड कांस्टैबुलरी को बाईपास करने का मंशा नहीं है और इसको बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार कृतसंकल्प है तो ऐसी हालत में उनकी सुविधाओं और सहूलियतों की व्यवस्था होनी चाहिए जोकि आर्मी को प्राप्त है। उनको वही हथियार मिलने चाहिएं जो कि आर्मी को मिलते हैं। काम उन से वह लिया जाय जो आर्मी से लिया जाता है। इसी तरह सारी दिक्कतें और परेशानियां उनको वही उठानी पड़ें जोकि आर्मी को उठानी पड़ती हैं लेकिन सुख, सुविधाओं और सहूलियतों में और उनकी सर्विस कंडीशंस में अन्तर हो तो यह बात ठीक नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर

ऐसी बौरडर सिक्योरिटी फोर्स बनानी ही है तो तमाम सुविधाएं जो आर्मी को दी जाती हैं वही उनको दी जांये । वही हथियार उनको दिये जांय जोकि आर्मी को दिये जाते हैं। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ओंकारलाल बोहरा (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मुझे भाई झारखंडेराय जी के भाषण को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ । उन्होंने सदा की भांति इस प्रश्न को भी राजनैतिक दृष्टि से देखने की कोशिश की। लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि संघीय शासन या प्रान्तीय शासन जैसी कोई बात इस बिल के साथ माननीय चव्हाण साहब के दिमाग में नहीं रही है ।

बौरडर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में यह सही ही कहा गया है कि उस को एक शक्तिशाली फोर्स बनाया जाय। मैं यहां पर यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इन पिछले 5-7 वर्षों में बौरडर पर छुटपुट घटनाओं और तनाव की स्थिति रही है उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा सामयिक और सराहनीय कदम है जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने उठाया है। जाहिर है कि हर समय हम मिलैटरी की भाषा में मिलैटरी की नदद नहीं ले सकते। लेकिन आज चीन ने जो तनाव पैदा किया, आज पाकिस्तान ने बौरडर में जो तनाव पैदा किया, यह हमारी सीमाओं पर जो छुटपुट घटनाएं और तनाव पैदा होता रहता है उसके लिए एक अलग सुरक्षा वाहिनी तैयार करने का जो फैसला किया है मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता थी।

पुलिस आंतरिक शांति कायम रखने का कार्य करती है, ला ऐंड आर्डर मैंटेन करने के रात, दिन के कामों में दिलचस्पी लेती है। हमारे दनिक प्रशासन में एक उसका उपयोग होता है और मिलटैरी युद्ध के समय बाह्य आक्रमण का सामना करने के लिए तैनात रहती है। इनके बीच में यह जो सुरक्षा सैनिकों की की एक कल्पना की गई है मैं समझता हूं कि यह उचित है।

आमतौर से चीन ने पिछले कई वर्षों से हमारी सीमाओं पर काफी तनाव पैदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा पाकिस्तान भी सदा तनाव पैदा करने की स्थिति बनाये रखता है। युद्ध की बात आज के विश्व में कोई बहुत आसान बात नहीं रह गयी है । युद्ध हर समय नहीं हुआ करता है और युद्ध का डंका हर समय नहीं बजा करता है । लेकिन जैसा मैंने पहले कहा हमारी सीमाओं पर आमतौर से शोचनीय सी स्थिति है, असुरक्षा की भावना विद्यमान है घुसपैठिये हमारे यहां आ जाते हैं या जासूसों का जाल हमारी सीमाओं के अन्दर आ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिये यह जो सीमा सुरक्षा सैनिकों की वाहनी की कल्पना की गई है मैं समझता हूं कि यह बड़ी उपयोगी है और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिये इसकी बड़ी महत्ता है । मैं इस बिल का समर्थन और स्वागत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले वर्षों में पिछले समय में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चिन्ताजनक स्थिति रही है और इसलिये हम जो भी क़दम उठा सकें वह हमें उठाने चाहिएं । साथ ही इस मसले को हमें राजनैतिक पहलू से नहीं देखना चाहिये । पूर्वोत्तर सीमा में, नेफा के आसपास के इलाकों में जैसी स्थिति है उसको देखते हुए हमें सीमा पर ऐसे शक्तिशाली सैनिकों की व्यवस्था रखनी है जिनके कि हाथों में हर तरह के आवश्यक शक्तिशाली हथियार आदि हों और सब तरह की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों । मैं इस सम्बन्ध में अपने गृह मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान के बौर्डर की ओर ले जाना चाहता हूं । राजस्थान का बौर्डर

[श्री ओंकारलाल बोहरा]

700 मील का है । जब यह प्रतिरक्षा मंत्री होते थे तो उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई में विजयोल्लास का डंका बजाया था । उस समय आप जोधपुर भी पधारे थे । उस समय आप ने महसूस किया था कि राजस्थान के बौर्डर पर जितनी सुरक्षा शक्ति रखने की आवश्यकता थी उतनी उन दिनों वहां पर नहीं थी और इसीलिए पाकिस्तानियों ने हमारी राजस्थान की जमीन में आने की हिमाकत की थी और जोधपुर तक उन्होंने बम बरसाये थे लेकिन जोधपुर के दिलेर नागरिकों ने बमों का वीरतापूर्वक सामना किया और अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और जोधपुर के सैनिकों ने दुश्मन को बढ़ने नहीं दिया । उस वक्त उन्होंने जोधपुर के सैनिकों को उनकी वीरता और अदम्य साहस के लिये बधाई दी थी । उसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय ने जो यह बौर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक सुरक्षा वाहिनी तैयार की है वह एक बड़ा सराहनीय क़दम है । मैं और अधिक न कहता हुआ बस कुछ सुझाव उसके बारे में हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

यह जो राजस्थान का बौर्डर है यह बिलकुल एक रेगिस्तानी इलाक़ा है । वहां पर मीलों तक पानी की व्यवस्था नहीं है । सड़कों की यातायात की सुविधा नहीं है । हमारे जो नागरिक वहां रहते हैं मैं समझता हूं कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिये भी हमें राजस्थान के उस बौर्डर पर सब तरह की सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिये । हम बौर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मातहत कितने ही सुरक्षा सैनिक क्यों न रखें लेकिन अगर उन इलाकों के रहने वाले मजबूत नहीं हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की मा ूल व्यवस्था नहीं है उनकी आजीविका और र ाने, पीने की यदि समुचित व्यवस्था नहीं है तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा वह क्षेत्र कमजोर पड़ जायगा ।

इसी प्रकार आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इलाके के अन्दर मीलों तक तोपबंदी कर रखी है लेकिन अभी हम लोग उतना न कर पा रहे हैं । उनके पास लम्बी मार की हथियार हैं जबकि हमारे सुरक्षा सैनिकों के पास इस तरह के हथियार नहीं हैं । आप बौर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से वहां सिपाहियों को लगायें लेकिन उनके लड़कों के लिये पढ़ाई की माकूल व्यवस्था नहीं है । आप उन्हें बौर्डर एलाऊंस नहीं देते हैं । जाहिर है कि यदि आप उनके बुढ़ापे में उनकी जमीनों की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उनके मन में जो कमजोरी होगी वह हमें ताक़तवर बनने से रोकेगी । मैं चाहता हूं कि बौर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिकों का रुतबा बढ़ाया जाय, उनको अधिक से अधिक हथियार दिये जायं और पाकिस्तान के सैनिकों के मुकाबले में उन्हें अधिक से अधिक हथियार व अन्य सभी आवश्यक सैनिक सामग्री देकर शक्तिशाली बनाया जाय ।

15.49 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इसके साथ ही साथ राजस्थान के उस रेगिस्तानी इलाके के अन्दर जहां मीलों तक पानी नहीं है वहां की जनता को आज आप जब तक सब आवश्यक सुविधाएं नहीं देंगे, यातायात आदि की सुविधाएं नहीं देंगे तब तक हमारी सीमा सुरक्षा का यह काम अधूरा बना रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । चाहे वह गुजरात हो, राजस्थान हो और चाहे वह पूर्वी क्षेत्र हो नेफ़ा हो यह सभी हमारी सीमाएं हैं और जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिये यह जो हमने सुरक्षा वाहिनी तैयार की है उसको अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिये ताकि यह आये दिन की सीमाओं पर जो होने वाली घटनाएं हैं उन को हम इस बौर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें और चूंकि इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है इसलिये मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have got a long list of speakers but because we have exceeded the time allotted, I will call the Home Minister now. I would, however, accommodate a few hon. Members at the time of the third reading.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to hon. Members who have participated in the debate during the first reading of this Bill. The appreciation that they showed about the organisation of the Border Security Force and the type of dangers that they will be exposed to is something which, I am sure, the officers and men of that force will gratefully remember because it is this body which is the ultimate sanction for what they have to do or will continue to do. When they know that the Members of Parliament are quite aware of the dangers that they are likely to face and that they are taking care of all the problems that they will be facing, it is something much more than a reward for all the dangers that they will ultimately face. It is for this reason that I must express my deep sense of gratitude to hon. Members.

Coming to the many points that were raised during the course of the debate, some of which are worth explaining, I would take some little time to explain some points in detail. Members asked me a question as to what ultimately is the role of this force; why we do not call it either a police force or an army; why we have made it some sort of an in-between thing. Well, Sir, it is not the question of nomenclature; ultimately, the character of a force is decided by the tasks that it is supposed to perform. This, really speaking, is the basic thing which we must not forget.

It is not a police force because it is not doing the police duty as we understand it; and it is not an army because it is not doing the army job. It is a fact of life. It is no use thinking as if there are two categories and every force must ultimately be catalogued under the one or the other. That would not be a right approach. Here is a task which is neither a police task nor an army task; it is a different task by itself. Our experience of the border problems of the last 20 years has contributed to the emergence of this police force. When I say 'police force', I mean the Border Security Force.

Before this force was constituted under the CRP Act on the 1st December, 1965, what was the arrangement? The arrangement was that the different States used to maintain some sort of a reserve police force or border police force which used to look after the task which the Border Security Force is supposed to look after and the Central Government used to bear the cost of the police force that the States used to maintain. As far as the cost part of it is concerned, it is quite all right. But I know from my own experience from the other end, because during that period I was working in the Defence Ministry, how difficult it was to co-ordinate the activities and to get them all working in a similar manner. It is absolutely a difficult task of co-ordination.

Therefore in the beginning of 1965 this question was very seriously considered and some study teams were appointed to go into all aspects of the problem. I think, by the month of May we had come to the conclusion that some other force must emerge out of these conditions. Some time in the month of June the then Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, called a conference of the Chief Ministers. It was a difficult task to get the consent of the Chief Ministers to release the State police forces and make it a Central responsibility. But I must say that the patriotic sense, the national sense, ultimately prevailed and all the Chief Ministers conceded that there should be a Cen-

[Shri Y. B. Chavan]

tral police force and that they were prepared to hand over this task to the Central police force. This Security Force was ultimately constituted in the month of December, 1965.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): The Congress was in power in all those States. The days have changed now.

SHRI Y. B. CHAVAN: I cannot help it. If the Congress can come back again, what can I do about it? Let us not go into that. (*Interruption*). What they did was the right thing. I am sure that if he were also the Chief Minister—I do not know whether that is going to happen any time—he would also agree to it.

SHRI JYOTIRMOY BASU: We would have security; I can assure you.

SHRI Y. B. CHAVAN: Thank you very much. Sir, the point that I was mentioning was that this was ultimately agreed to and this force came into being. What is the task of this force? Let us come to that. Although it is nearer the task of the army, yet, I must say that, with all the emphasis at my command, it is not yet the army. I know it is exposed to a certain extent to the same dangers that the army faces, in the beginning. I have no doubt about it. But as far as the tasks are concerned, they are completely different tasks, qualitatively different. Let us understand that when we are thinking about the character of the force, we must be very accurate, precise and objective in the tasks that they will be required to perform. It is true, as some Members said, that they will be the first line of defence in a sense, yes, because, the first impact of any aggression, the first brunt, will have to be borne by the Security Force. But that is all. Certainly, at that time, they will be asked and are expected to take the first brunt, but they will not be expected to strike back in the same way as we expect the army to do.

Some Members said that, "Well what will happen during this time the army will come." This is really speaking the very life of the whole organisation. If there is no co-ordination between the Border Security Force and the armed forces, if there is no intelligence with the Border Security Force and the army, well, the whole machine fails; the whole Government fails and the whole country fails. We are not talking about the failure of the army, the failure of the Border Security Force or the failure of the country or its intelligence. It is not likely to happen. But it is true that the first impact will have to be borne by them. So, I concede that they must be given such arms as are necessary and as will enable them to bear this first brunt. This is certainly an accepted fact. The types of weapons that are being given are given from this consideration only, because, at the present moment, they are given these ordinary rifles; they are given the LMGs and the MMGs, machine-guns and mortars, .303 bore. These are really speaking basically the infantry weapons. Some Membrs said whatever arms which are obsolete in the army are given to them. I would say that this is a thing which is not based on facts.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Are these rifles semi-automatic?

SHRI Y. B. CHAVAN: The army has got the .303 weapons.

SHRI S. S. KOTHARI: With these outdated weapons, we fought against China and we failed.

SHRI Y. B. CHAVAN: At the same time, you do not give to this force the same type of weapons or machines that the army has. As our availability grows, naturally, some weapons will be replaced. That is always a continuing process. For example, the LMG, the MMG and the mortars are the same as the army has. On no consideration can we say

that the LMG, the MMG and the mortars are of obsolete types. It is not. So, arms are being given. I agree and I must concede. I am very glad that this House is very conscious of the fact that this force will have to be given continually modern arms, good arms, effective arms. And as one responsible for this hon. House, I will assure this hon. House that this aspect will be very carefully kept in mind constantly by the Government. It is not made a question of the life of those people who are defending there. That is, certainly, a primary and vital question. But, at the same time, it is a question of enabling them to fulfil the task for which they are there. That is really more important.

16 hrs.

SHRI BAL RAJ MADHOK: That demands mobility also.

SHRI Y. B. CHAVAN: I am coming to that.

SHRI JYOTIRMOY BASU: You have employed the Border Security Force to face mass agitations, political agitations and all that.

SHRI Y. B. CHAVAN: I am coming to that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No interruptions.

SHRI Y. B. CHAVAN: This is the type of their thinking. They only take the Government to be their enemy. They are not bothered about other enemies.

SHRI JYOTIRMOY BASU: We are not isolated from the people such as you are.

SHRI Y. B. CHAVAN: As long as you will remain in that wonderful misconception I am safe. If that is the misunderstanding in which you want to keep yourself, I am safe.

Now, about the question of mobility, of course, the mobility that will be expected of the Army and of the Border Security Force are two different things. At the same time, it is quite necessary that they must have proper vehicles. The proper vehicles are given to them. Of course, there may be some deficiency about the number of vehicles. It will certainly, be looked into.

Some hon. Members mentioned about binoculars. There is some deficiency of binoculars. But they are being replaced and some are being got from Defence. They will be given to them. I would like to mention that the entire Border Security Force has got a communication system of its own. Its headquarters here will get information of what is happening on the border within the minimum possible time. I do not want to mention what time it will take. Because of this communication system, there is a possibility now of proper coordination between the different Forces and the coordination between the armed forces and the Border Security Forces as well.

Some hon. Members mentioned about intelligence. About intelligence, I must say that there is always some sort of misconception about this matter of intelligence. Some people say there is military intelligence, there is basic intelligence and there is border security intelligence. What is intelligence? This question has been many times discussed in this honourable House before. I have had occasions to make a mention of it. Every piece of information is not intelligence. Intelligence is a very well-evaluated information. Its importance, its correlation to certain situations has to be gone into. It has to be related to political factor and many other facets of national life. Therefore, military intelligence also is a part of general intelligence. It is intelligence that matters. The Border Security Force, certainly, has its own intelligence arrangement. But it is not an intelligence organisation by itself. It, certainly, looks after

[Shri Y. B. Chavan]

certain aspects of intelligence. The Border Security Force, sitting on the border of a country does collect intelligence. If I may try to illustrate it, it sits there physically with its ears open and with its eyes open. It sits behind and it sees ahead. It tries to get information and tries to coordinate with what the Army is supposed to do. It certainly gets to know what is the people's thinking on the other side and what is the people's thinking amongst whom they are working. This is also a part of intelligence. They, certainly, look after certain aspects of intelligence. Therefore, I can say that they have got their own arrangement of intelligence. It also will have to be improved from time to time. They also will have to be given certain means and certain services for this type of work.

About training, we can, certainly, have some sort of reformed pattern of organisation, uniform pattern of weapons and uniform pattern of training. We have got 3 centres at Tekanpur, Hazaribagh and Indore.

The hon. Member belonging to the Swatantra Party, Shri Somani, raised a very intelligent and interesting point. He asked: 'if you have got these three general training camps, what about the peculiar pattern or peculiar problems of certain regions?'; the border security force will have to face a different problem in Rajasthan, a different problem in Kashmir and so on: terrains are different, climates are different; many other things are different. I think, he was right. But I can only assure him that this was very well anticipated by the border security force and its organisers. Besides these three important centres, there are also such centres which look after the special aspects of the terrains, the problems of borders, etc., and we have got about eight such centres. I do not want to mention where they are. We have got eight different centres in different sectors which would look after the special problems of those areas and special trainings are undertaken from time to time.

Some members spoke about recruitment. I do take note of what my hon. friend, Mr. Abdul Ghani Dar, said. What he said was very legitimate and I do take note of it. We are taking note of it and trying to do what we can in all sectors of services, including border.

Somebody suggested that recruitment should be made from the local areas. Recruitment should be made from all areas; I quite agree to that. But one cannot say, and I personally do not subscribe to that position, that people recruited from Rajasthan alone should be posted on the borders of Rajasthan. If that is suggested, I do not agree, but I quite agree that there are certainly some people who have got special aptitude for this and they should be given more opportunity. I understand that, and such efforts are being made. Practically we recruit and train every year nearly 7,000 people. From the present recruitment going on, I can say that most of the recruitments are done from different parts of the country. These three centres are feeded by recruitment centres and they are being trained in that manner.

Some members mentioned about pay and service conditions. I was very glad that hon. Member Shri Fernandes—he is not here—was in the company of the border security force for nearly 24 hours, and as a good trade union worker he has gone into the problems of pay, allowances, pay-scales, service conditions, rest hours, leave period, etc., etc. I can tell him that he has certainly raised very important points and we are considering those points.

SHRI RANDHIR SINGH: I raised those points. He spoke later. He just repeated what I said. I spoke with greater vehemence.

SHRI Y. B. CHAVAN: I have not yet completed. You are in a hurry for being mentioned.

He was thinking that he gathered information from them without their knowing about it. But I must pay compliments to the border security people also. Without Mr. Fernandes knowing about it, they have completly brain-washed him in this matter. He was even prepared to take the case of supply of liquor. He unnecessarily blamed the Gujarat Government for that. I must tell him that this has not been taken up with the Gujarat Government yet.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : क्या उन को गुजरात में नहीं देना है और दूसरी जगह देना है ?

SHRI Y. B. CHAVAN: At the present moment, it has not been supplied there because naturally we have to take it up with the State Government as it involves the question of exemption of certain taxes. In the other areas, it was going on, but as this is a very strictly prohibited area, this matter is yet to be taken up with the Gujarat Government. They have not said 'no'. I am sure if the Director General and other people of the force decide to raise those problems with them, the Gujarat Government will, and should, sympathetically consider these approaches.

I am glad that Shri Randhir Singh and other members also raised the question of pay scales and other matters. This is natural for Shri Randhir Singh as he comes from an area from where not only in the army but in this force there are large number of people recruited. He himself is a born fighter and if he were not here, I am sure he would have been in the Border Security Force.

SHRI RANDHIR SINGH: I am grateful.

SHRI Y. B. CHAVAN: I know he wanted it.

I am grateful to other members also who made a mention of service conditions of the force.

I must come back to the other criticisms. Some members raised the question of housing. I must clear one point here. We have got a chain of battalion headquarters all along the border and we have taken up a well-planned housing programme in these headquarters. Of course, it will take quite a long time to be completed, because suddenly the border security force has leapt into quite a big size. This year our plan is to have a building programme costing a crore of rupees. I hope I will get more and more money so that I can complete the programme at least within ten years. If I could do it, I can say that this problem will have been very well solved.

SHRI BALRAJ MADHOK: But they are putting up the headquarters or quarters quite in the interior. This force has to work primarily in the border areas and therefore, their quarters should be near about the border.

SHRI Y. B. CHAVAN: Not very much in the interior. But it is not very much on the border, because it should not be. Take, for example, Jodhpur. In the same way, all along the border there is a chain of battalion headquarters, and naturally they should not be near the border.

SHRI BALRAJ MADHOK: Not very near.

SHRI Y. B. CHAVAN: It should not be in Delhi, for example. It should not be in Lucknow or Kanpur or Bengal and it should not be in Assam with the men in Bengal. This was one point mentioned. So I thought I should explain it.

SHRI ONKARLAL BOHRA: Rajasthan?

SHRI Y. B. CHAVAN: He mentioned about Rajasthan, the road difficulties there and so on. A well-planned road programme has been taken up. I think it is being implemented gradually.

SHRI ONKARLAL BOHRA: Drinking water?

SHRI Y. B. CHAVAN: Now I will come to the question of the draft. Some members made the point that this is very loosely drafted. I think the hon. member, Shri Gupta, mentioned it. I would like to say that no section of this Act is just originally drafted except when it was absolutely necessary where it related to the name, the Border Security Force etc. Every section has been taken literally either from the Air Force Act or the Army Act. If you see the Air Force Act of 1950 or the Army Act of 1950, you will find word for word the same sections. Therefore, when I said I was not ready to go to the Select Committee, it was not that I was not prepared to go into the well-balanced phraseology of this legislation. But it was deliberately done. It was done on this basis that their tasks are much nearer the army's. So, this Chapter in the Bill should be framed on the same lines. Secondly, the standards of implementation and the standards of interpretation will be easier if it is drafted in the same way as the Air Force Act or the Army Act.

The hon. member asked why there should be words like "shamefully", "treacherously" etc. These words are not used against the force as such. They are used about certain activities. For example, the word "shamefully" is used in Clause 14 of this Bill. It reads:

> "Any person subject to this Act who commits any of the following offences, that is to say,—
>
> (a) shamefully abandons or delivers up any post, place or guard, committed to his charge or which it is his duty to defend; or"
>
> * * * * *
>
> (d) treacherously holds correspondence with, or communicates intelligence to, the enemy or any person in arms against the Union; or"

SHRI INDRAJIT GUPTA: Can he communicate with the enemy otherwise?

SHRI Y. B. CHAVAN: I will come to that. I want to go into that matter and convince you if I can. First of all, let me tell you that these clauses are taken from other Acts. For example, Section 34 of the Air Force Act says:

> "shamefully abandons or delivers up any garrison, fortress, fort etc."

Clause 14(a) in this Bill is verbally on the same lines.

श्री अब्दुल गनी डार : लेकिन वह एक्ट श्री चव्हान का तो नहीं बनाया हुआ है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: यह 1950 में बना हुआ है, इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ है । मेरा तो नहीं, लेकिन इस पार्लियामेंट का बना हुआ है ।

श्री अब्दुल गनी डार : लेकिन आज तो चव्हाण हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चव्हाण को भी दुनिया के पहले इतिहास को लेकर चलना पड़ता है ।

SHRI TENNETI VISWANATHAM: The clause says "shamefully". Supposing it is "shamelessly"? what is the difference? The fact is, the word is superfluous.

SHRI Y. B. CHAVAN: Why don't you allow me some time? If you do not want to agree, do not agree.

Similarly, in Section 34 of the Armed Forces Act the same wording is used.

Communication with the enemy sometimes has to be done. Suppose there is a commanders' conference. He is himself a good student of law.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I never studied law in my life.

SHRI Y. B. CHAVAN: That is why the whole mistake has been made.

In order to prove a criminal offence, what is more important is the *mens rea*. These are the basic concepts of jurisprudence. Leaving a post sometimes is done when he has made a proper judgment that it was in the interests of the force to leave it. Leaving a post shamefully is different. So, the whole thing will have to be ultimately judged by the circumstances and the evidence available. It is not merely leaving the post. The punishments which are provided are severe. Therefore, we have to provide these words. They are not provided as a piece of literature. They are provided to indicate a higher degree of proof of the offence. The hon. member said that we normally say "strong reason to believe". We may say many things, but here we are talking about the law. It mentions here "grave reason" where summary proceedings have to be started, and when summary proceedings have to be started, there must be very important reasons for it. "Grave reason" shows a higher degree of reason. These words are used in Section 120 of the Air Force Act itself.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Where was it borrowed from? From the 19th century?

SHRI Y. B. CHAVAN: Everything that comes, comes from behind that is what the Sanskrit saying tells us. I cannot say where it was borrowed from. Let us at least borrow from what this Parliament passed in 1950. But we are not borrowing it merely for the sake of borrowing. These are three different forces which are the most important forces; whose tasks are of the same type. So, the discipline is also expected to be uniform and the standard of implementation of that discipline must also be framed in the same phraseology. This is the explanation.

This Bill was drafted very carefully—not loosely or without any consideration. It was considered in all its aspects at all levels of our security force. Prof. Ranga yesterday asked whether it was considered by the officers of the Force. The Bill was sent down to the battalion level and the battalion commander was asked to discuss the contents of it with the NCOs and JCOs. They set together and discussed. We have tried to go into this as much as we can and we have examined all the details.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): The refugees of West Pakistan. . .

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not want to go into that now; this Bill is not dealing with refugees.

SHRI RANGA (Srikakulam): Difference in the status of the army personnel and this force?

SHRI Y. B. CHAVAN: The presumption is that the dangers that the Army men have to face are a little graver than those of these people. There is no question of any status. To me, the status of a person in the Army or in the border security force or in the ordinary police force is the same. The dignity of every citizen of India in whatever profession is the same. But the degree of danger to which a person who is in the war is exposed is greater than a person in the border security force.

श्री झारखंडे राय : उत्तर प्रदेश में बाराहोती में पी० ए० सी० और आर्मी दोनों काम करती हैं । तो वहां पर अब इसके बनने के बाद पी० ए० सी० का क्या होगा ?

SHRI Y. B. CHAVAN: In Bara Hoti there is no border security force; there is some other force, the other police force.

श्री हंबर लाल गुप्त : ऐसा क्यों ? यहां मैं पूछना चाहता था । बाकी बार्डर पर क्यों नहीं है ?

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not want to answer that question this way. I should like to explain it to him sometime. But the point is that the law is very clear. The border security force can be given a charter to go to that border. What is in the Statement of Objects and Reasons makes a reference to the existing BSF. Some Members mentioned it yesterday. They mentioned the Burma border also. These tasks can be enlarged or changed. But the charter which this Bill gives them is the security of all borders.

SHRI HEM RAJ: Indo-Tibetan police?

SHRI Y. B. CHAVAN: It can be covered but at present they are not. This law provides for their going to any border. I am sorry I could not accept the suggestion to send this to a Select Committee because it is not necessary. I am not afraid of the Select Committee. I am convinced it is not necessary.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are two amendments to the Motion for Consideration seeking to refer the Bill to a Select Committee by Shri George Fernandes and Shri Kanwar Lal Gupta. I shall put them first to the vote of the House.

Amendments Nos. 1 and 2 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the constitution and regulation of an Armed Force of the Union for ensuring the security of the borders of India and for matters connected therewith be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2— (*Definitions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take the Bill clause by clause. There is one Government amendment to clause 2.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): I move amendment No. 13.

Amendment made

Page 3,—

for lines 23 to 27 *substitute*—

'(W) "superior officer", when used in relation to a person subject to this Act, means

(i) any member of the force to whose command such person is for the time being subject in accordance with the rules;

(ii) any officer of higher rank or class or of a higher grade in the same class;

and includes when such person is not an officer, a subordinate officer or an under-officer, a higher rank, class or grade;' (13)

(*K. S. Ramaswamy*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clauses 3 to 6 were added to the Bill.

Clause 7— (*Liability for service outside India*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is any amendment being moved to clause 7?

SHRI JYOTIRMOY BASU: Sir, I want to move my amendment No. 16.

SHRI ABDUL GHANI DAR: I want to move amendment No. 15, standing in my name.

Page 5, line 2,—
add at the end—

"in case defence of the country requires his services". (15)

جناب میری امینڈمینٹ بڑی سیدھی سادی ہے ۔ میں نے بھائی چھاگ صاحب سے عرض کی تھی لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی ۔ میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہوم کا تعلق ملک کے اندرونی معاملوں سے ہے، آؤٹ سائڈ انڈیا سے نہیں ہے، اسلئے اس کو صاف طور پر واضح کر دیا جائے - ورنہ پولیس پولیس میں چلتی ہی ہے ڈفینس اور ہوم منسٹر میں نہ چل پاوے - اسلئے میں نے یہ عرض کی تھی - میں نے اپنی امینڈمنٹ میں صرف یہی چاہا ہے کہ اگر خاص موقعہ پر انکو ایسا کرنا پڑے تو کریں - ورنہ یہ انکی ڈیوٹی نہیں ہے - ملک کے اندرونی بچاؤ کیلئے تو وہ کریں لیکن باہر کیلئے ملٹری کی سروسیز لی جاتی ہیں - میں نے یہ بڑا سادھارن سجھاؤ دیا ہے چوہان صاحب اسکو منظور کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی -]

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put amendment No. 15 to the vote of the House.

Amendment No. 15 was put and negatived.

SHRI JYOTIRMOY BASU: I beg to move:

Page 5,—
after line 2, *insert*—

"Provided that a member of the Force shall not be ordered to be on active duty in any part of the territory of India which is more than five miles from the border." (16)

The duty of the Border Security Force is on the border. We want to safeguard the border. So, we have constituted this Force, as Shri Chavan has been saying again and again. It should not be used as the Central Police Force or Central Security Force. We now see that the strength of the Border Security Force is in-

[Shri Jyotirmoy Basu]

creasing and we are spending more money. Its budget has gone up from Rs. 4½ crores to Rs. 62½ crores, as I mentioned yesterday.

When Shri Dalai Lama is buying tea gardens on India-China border with CIA help, Shri Chavan has no time to prevent that. Perhaps, it does not suit them. That is why I say that the Border Security Force is raised to strengthen the hands of the Central Government. Internal crime is increasing in Delhi and West Bengal. In Park Street, the heart of Calcutta, Rs. 5 lakhs was robbed in the broad day light and they could not catch even the tail of a single criminal. Now you have raised this Border Security Force and trained them by spending more money. You have now a vast border security force by spending about 14 times of what you spent ten years ago. Yet, smuggling is on the increase on all the borders. Areas adjacent to the borders are the smugglers' paradise.

Therefore, my reading of the Border Security Force, or Industrial Security Force or the Central Police Force—they are all the same stuff—is that they are forces for the security of the Central Government, under different shoulder badges, as they call it in the army. In West Bengal my poor minority friends in districts of Nadia and Murshidabad get panicky when they see the Border Security Force moving about. They go to the villages and demand ransom. If their demands are not met the villagers are terrorised, or put behind the bars or thrown beyond the borders.

I again insist upon the Congress Party and Shri Chavan either to accept my amendment or to change the name and call it the Central Security Force.

DR. RANEN SEN (Barasat): I support this amendment moved by Shri Basu. I come from a constituency which has a large border with East Pakistan. Three *thanas* are on the border of East Pakistan. So I know a little bit of what is happening here. There are Border Security Forces there.

While Shri Chavan was speaking just now he said that the headquarters will be situated not at the border but a little away from the border. I want to know why the main force of the Border Security Force is situated near about Calcutta which is 40 to 45 or 50 miles away from the Indo-Pak. border.

In the report submitted by the Home Ministry during the last Budget session it has been stated that the border security forces have been used to quell civil disturbances in many States. As far as our State of West Bengal is concerned, we have seen times without number that the Border Security Force has been deployed to quell civil disturbance or to forestall any civil disturbance which according to the Government of India was coming. When the Ajoy Mukerjee Ministry was being dismissed, 24 hours before the dismissal the Border Security Force was brought to Calcutta and deployed all over West Bengal. This is from our personal experience and we know it. Therefore when this amendment says that this Force shall not be ordered to be on any active duty in any part of the territory of India which is more than five miles of the border, there should be no difficulty for the Home Minister to accept it because in the aims and objects of the Bill it is stated that the purpose of this Border Security Force is to guard the border of India and he has said that at present they are guarding the border between India and Pakistan. Therefore, I do not think that it should be difficult for Shri Chavan to accept this amendment.

SHRI JYOTIRMOY BASU: If he really wants to make it a Border Security Force.

SHRI Y. B. CHAVAN: I really wanted to reply to this point in my earlier speech but then I knew that the hon. Member wanted to move the amendment and that will be the

occasion for me to reply to it. I will certainly meet his main point later, but he mentioned about smuggling and said that there is much smuggling going on and the Border Security Force is not doing anything about this. I wanted to mention about it in my previous speech but I could not do so. I may now say that since the Border Security Force has come into existence it has done some good work and I would like the House to know about this. In 1967 smuggled goods worth Rs. 5,60,000 were seized by the Force on different occasions.

AN HON. MEMBER: Only.

SHRI Y. B. CHAVAN: They had to face clashes; there were occasions for exchange of fire and nearly 23 smugglers were shot dead. It is not a question of merely 'only' or 'not only'. This certainly shows that they are alive to it. Some of the members of the Border Security Force were injured in these clashes and—I have not got the figure—it is quite possible that some of them must have lost their lives too.

SHRI JYOTIRMOY BASU: That is a showroom performance.

SHRI Y. B. CHAVAN: I am glad, you are not the judge to decide that.

The hon. Member says that the Border Security Force should be allowed only up to 5 miles of the border. Why? Because he or his friends want to create chaos in the country and such forces are an inconvenience to them.

DR. RANEN SEN: There is the ordinary police force; why use the Border Security Force?

SHRI Y. B. CHAVAN: When a certain situation arises on the border even forces which are not the Border Security Force will be taken there. Even now some of the battalions of the CRP, whose job is not under this Act but whose job is something else, which was supposed to look after internal security, are working in Manipur, Mizo areas and some difficult areas. They are working there. Even the army is supposed to come and give aid to the civil power, civil authority. What is wrong, therefore, if the Border Security Force is called? (*Interruption*)

SHRI JYOTIRMOY BASU: The cat has come out of the bag now!

SHRI Y. B. CHAVAN: The major task of this Force is to ensure security of the borders of our country. Occasionally, if they are asked to render any other help, it will be within their duty to perform.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put the amendment to the vote.

Amendment No. 16 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 to 12 were then added to the Bill.

Clause 13— (*Restrictions respecting right to form association, freedom of speech, etc.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are two amendments. Mr. Salve is not here. Shri Abdul Ghani Dar—is he moving his amendment?

श्री अब्दुल गनी डार : जी हाँ ।

जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो यह रखने जा रहे हैं कि जो फोर्स हो उनका पालिटिक्स या सेमी-पालिटिक्स में कोई भी हिस्सा न हो तो मैं ने अर्ज किया यह मुनासिब नहीं है । और उससे ज्यादा जो मेरे लिये मुश्किल है वह यह है कि ये कहते हैं कि किसी बात पर झगड़ा हो, वह चीज सोशल हो या न हो, रेलिजिस हो या न हो, पालिटिक्स से भी उसका कोई ताल्लुक न हो लेकिन गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वही फाइनल होगा । मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है । इसलिए किवही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे; उनका मेरे कत्ल का दावा करें किस पर ।

एक माननीय सदस्य : ये किस पर बोल रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has an amendment.

SHRI ABDUL GHANI DAR: I beg to move:

Page 6, for line 19, *substitute*—

"Central Government shall decide the disputed parts which may be challenged in the Supreme Court and the Supreme Court's verdict shall be final."

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह फैसला गवर्नमेंट को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह झगड़े की बात है, गवर्नमेंट और सिपाहियों के दरम्यान। वे यह समझ सकते हैं कि यह रेलिजस या सोशल फंक्शन है, इसमें पालिटिक्स का कोई दखल नहीं है लेकिन मंत्री जी यह कहते हैं कि अगर झगड़ा हो जाए तो हमारा फैसला ही फाइनल होगा। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है आप अपने हाथ में इस चीज को क्यों रखना चाहते हैं, आप क्यों पावर सेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं। ऐसा फैसला तो एक अदालत ही कर सकती है। अदालत को ही उसका फैसला करना चाहिए। गवर्नमेंट को या डाइरेक्टर, जिसको कि आप मुकर्रर करने जा रहे हैं उसके हाथ में फाइनल फैसला नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि चव्हाण साहब उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज करने की इजाजत दें ताकि वहां पर वे अपनी बात कह सकें और बता सकें कि सरकार का नजरिया क्यों गलत है।

[شری عبدالغنی ڈار : جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو یہ رکھے جا رہے ہیں کہ جو فورس ہو ان کا پالٹکس یا سیمی پالٹکس میں کوئی بھی حصہ نہ ہو تو میں نے عرض کیا یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے زیادہ جو میرے لئے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بات پر جھگڑا ہو، وہ چیز سوشل ہو یا نہ ہو ریلجس ہو یا نہ ہو پالٹکس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہ ہو لیکن گورنمینٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا - میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے - اس لئے کہ اگر ہم میرے قتل کا دعوہ کریں کس پر - وہی قاتل ،وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے . . .]

ایک مانلیئے سدسیہ : یہ کس پر بول رہے ہیں -

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has an amendment.

SHRI ABDUL GHANI DAR: I beg to move:

Page 6, for line 19, *substitute*—

"Central Government shall decide the disputed parts which may be challenged in the Supreme Court and the Supreme Court's verdict shall be final."

شری عبدالغنی ڈار : تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فیصلہ گورنمینٹ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیئے کیونکہ یہ جھگڑے کی بات ہے گورنمینٹ اور سپاہیوں کے درمیان وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ریلجس یا سوشل فنکشن ہے اس میں پالٹکس کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن منتری جی یہ کہتے ہیں کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو ہمارا فیصلہ ہی فائنل ہوگا - میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ موجود ہے - آپ اپنے ہاتھ میں اس چیز کو کیوں رکھنا چاہتے ہیں - آپ کیوں پاور سنٹرلائز کرنا چاہتے ہیں - ایسا فیصلہ تو ایک عدالت ہی کر سکتی ہے - عدالت کو ہی اس کا فیصلہ کرنا

چاہیئے اور گورنمنٹ کو یا تو ڈائریکٹر جس کو آپ مقرر کرنے جا رہے ہیں اس کے ہاتھ میں فائنل فیصلہ نہیں ہونا چاہیئے - میں چاہتا ہوں کہ چوہان صاحب ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی اجازت دیں تاکہ وہاں پر وہ اپنی بات کہہ سکیں اور بتا سکیں کہ سرکار کا نظریہ کہیں غلط ہے -]

SHRI Y. B. CHAVAN: I may explain it. This is regarding the right of the members of the force to belong to an association or a trade union. This sort of section was included in the other Acts connected with the police force, etc. Here, what we have said formerly was that he can be a member of a welfare association; whether that association or organisation is social, religious, etc., on that, there can certainly be a doubt. The question is who should decide about it. The hon. Member wants to make it justiciable so that it can be taken to the Supreme Court. This is a matter of authority of the Central Government and it is the right authority.

SHRI FERNANDES *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are on clause 13, amendment 17. You are supporting the amendment?

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मैं अमेंडमेंट को तो सपोर्ट करता हूं लेकिन इस पूरे क्लाज का विरोध करना चाहता हूं । मेरा कहना यह है कि यह जो क्लाज है इसको पूरा हटा देना चाहिए । उस किस्म का अमेंडमेंट तो इस वक्त नहीं है फिर भी मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे इसको वापिस लें । हिन्दुस्तान में आज एक करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं जिनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिये जाते हैं । वे अपना संगठन तो बना सकते हैं लेकिन उनके लिये किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना या उनकी मीटिंग्ज में जाना मना है । इस बात की कोई नयी जानकारी देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं । अब जहां तक पुलिस और पलटन वालों की बात है, वे राजनीतिक पार्टी के मेम्बर बनें या न बनें इस पर तो एक लम्बी बहस छिड़ सकती है इस देश में लेकिन उनको एसोसिएशन और यूनियन्स का सदस्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मैं समझता हूं इस पर कोई लम्बी बहस करने की आवश्यकता नहीं है ।

हम इस सदन में बोलते समय या इस देश में प्रजातन्त्र के बारे में बहस करते समय कुछ ऐसे देशों का उदाहरण देना सीखे हैं जिनको कि कुछ लोग आदर्श मानते हैं हालांकि मैं उनको आदर्श नहीं मानता हूं । जर्मनी का उदाहरण काफी बार दिया जाता है । पश्चिम जर्मनी से हम हर किस्म का सम्बन्ध रखते हैं और मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी इस बात को कबूल करेंगे कि पश्चिम जर्मनी में उस किस्म का प्रजातन्त्र चल रहा है जिसको वे पसन्द करते हैं । दूसरा उदाहरण इजराइल का दिया जाता है । दोनों तरफ के लोग कहते हैं कि इजराइल कितना अच्छा देश है, किस ढंग से समाजवाद बना रहा है और किस ढंग से अपना काम कर रहा है । इन दोनों देशों को एक आदर्श प्रजातांत्रिक देश कह कर कई बुद्धिजीवी लोग एकेडेमिक और राजनीतिक बहस चलाने का काम करते रहते हैं जिनमें से मैं समझता हूं, गृह मंत्री जी भी एक हैं । अब इन देशों के उदाहरण ही **मैं गृह मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । पश्चिम जर्मनी को जो पूरी पलटन है, रेगुलर आर्मी वह ट्रेड यूनियन की मेम्बर है । वहां की जो पब्लिक सर्विस यूनियन्स हैं उसमें वहां के झाड़ू लगाने वाले से लेकर पायलट तक और अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर राजदूतावासों में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स तक सदस्य हैं । लेफ्टिनेंट कर्नल की**

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

रक तक के लोग इसके सदस्य हैं । पूरी एक मजदूर यूनियन है, कोई एक अलग यूनियन नहीं है कि पलटन वाले कोई एक एसोसिएशन बना कर साल में एक बार उसकी साल गिरह मना लें बल्कि वह एक रेगुलर बारगेनिंग ट्रेड यूनियन है जिसमें तमाम किस्म के सारे क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सदस्य हैं । लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि आपकी पल्टन की रैंक के अन्दर मेजर-जनरल तक पहुंच जाता है तो मेजर जनरल से लेकर मामूली जवान तक, सभी लोग ट्रेड यूनियन के सदस्य बन सकते हैं काफी आन्दोलन के बाद साल डेढ़ साल पहले ही यह अधिकार दिया गया है । मेरे खयाल से वहा पर जो प्रजातन्त्र चल रहा है उस प्रजातन्त्र को उससे कोई भी धक्का नहीं पहुंचा है और न आगे ही पहुंचने वाला है । पलटन में काम करने वाले लोगों को अपनी यूनियन का सदस्य बनने का अधिकार देने से ।

वही हालत इजराइल की भी है । वहां तो जो पलटन का कमांडर इन चीफ है, जो कि फौज का सब से बड़ा अफसर है जैसे कि यहां पर कुमारमंगलम साहब हैं, वह भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, जवानों की बात तो अलग छोड़िये । यह कोई वालन्टियर आर्मी की ही बात नहीं है बल्कि जो स्टैंडिंग आर्मी है, लगभग दो लाख की जो रेगुलर आर्मी है उसके तमाम जवान और अफसर, कमान्डर इन चीफ तक, सभी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, मजदूर दल के आन्दोलन के सदस्य तो हैं ही । इससे वहां के प्रजातन्त्र को कोई धक्का पहुंचा है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई उदाहरण गृह मंत्री जी वहां पर पेश करेंगे । हमारे देश की हालत तो यह है कि अगर यूनियन बन गई है और कोई हड़ताल हो गई तो फिर हिन्दुस्तान का प्रजातन्त्र धोखे में हो जाता है जब कि एक महीने के लिए सारा फ्रान्स बन्द हो जाता है लेकिन वहां का प्रजातन्त्र धोखे में नहीं होता । हमारे यहां के बुद्धिजीवी लोग तो यह समझते हैं कि अगर झाड़ू लगाने वालों की भी हड़ताल हो गई तो हिन्दुस्तान का प्रजातन्त्र धोखे में चला गया । यहां पर ऐसा सड़ा हुआ बुद्धिजीवियों का दिमाग है जिसको साफ करना बहुत जरूरी है । इसलिए गृह मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस क्लाज को हटा दें या कम से कम तब्दील करने की बात करें । मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं आपके सामने मोटी बात रखना चाहता हूं कि एक जवान पलटन में भर्ती हो गया, अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया, अपनी जान को खतरे में डाल कर देश की सेवा करने के लिए तैयार हो गया तो उसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता है कि उसका शोषण करने का अधिकार राज्य सत्ता को चलाने वाले लोगों के पास आ गया । यह उसका मतलब कतई नहीं हो सकता है । उसको यह सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिएं जो समाज के दूसरे क्षेत्र के लोगों को दी जाती हैं । मुझको जब 8 घंटे काम करने के बाद अलग-अलग किस्म की सुविधायें देते हो तो उनको भी वह सब सुविधायें दो । जब देश में सामान्य किस्म का काम करने वालों को आप सुविधायें देते हैं चाहे वह लोक सभा के सेक्रेटेरियट में काम करते हों, दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के सेक्रेटेरियट में काम करते हों या किसी किस्म के दफ्तर में अथवा छोटे बड़े सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों धंधों में कर्मचारियों के तौर पर काम करते रहे हों, उन लोगों को आप जिन जिन चीजों की सुविधायें देते हैं वही सुविधायें इन बौरडर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को भी आप दीजिए । अनुशासन आप उनमें रखिये और उसके लिये आगे क्लाज आने वाला है जिसमें आपने यह रखा है कि जो गद्दारी करे उसे गोली मार दी जाये । गद्दारी के लिये आप मौत की सजा रख रहे हैं मुझे मंजूर है । अनुशासन बनाये रखने के लिये काम के बारे में, निष्ठा के बारे में और यह कि वह गद्दारी न करे इसके बारे में जो भी खबरदारी आप करना चाहें वह करिये ।

लेकिन यह उचित न होगा कि उन्हें उन सुविधाओं से वंचित रखा जाये जो कि अन्य कर्मचारियों को मिल रही हैं ।

देश के कल्याण और सुरक्षा के लिए वह एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं । उनकी मेहनत की बदौलत हमारे यहां संसद् में बैठ कर गम्भीर बहस करें, लम्बी चौड़ी बातें करें, वह वहां मेहनत करते रहें और हम यहां मेम्बर्स लोग अपनी सैलरीज एलाऊंसेज और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनायें और वह पार्लियामेंटरी कमेटी अपनी सिफारिश करने के लिए देश का चक्कर भी मार रही है, यहां दिल्ली में बैठ कर वह फैसला नहीं कर पा रही है, गरज यह कि हम अपने लिए तो सब तरह की बढ़ोतरी और सुविधाओं को बढ़ाने की सिफारिश करें लेकिन उन सीमा सुरक्षा सैनिकों को सुविधाएं व अधिकार देने से इंनकार करें और यह चाहे कि वह किस संगठन के द्वारा उसके लिए आवाज न उठायें तो यह सरासर नाइंसाफी है और इसलिए इस क्लाज का मैं सख्त विरोध करता हूं ।

SHRI Y. B. CHAVAN: This matter has been discussed many times on the floor of this House when we discussed similar Bills. I have got a fundamental difference of opinion with the hon. Member here. The question is whether the members of Armed Forces and Services should be allowed to become members of a party. In the type of political government that we have, in the type of political democracy that we are working here, I think it is not suitable; I have no doubt about that in my mind. The democracy of West Germany or the democracy of Israel is not my ideal. If it is Mr. Fernandes' ideal, he may adopt it.

Therefore, Sir, I oppose it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I shall put Mr. Abdul Ghani Dar's amendment, Amendment No. 17, to the vote of the House.

Amendment No. 17 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 13 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14—(*Offences in relation to the enemy and punishable with death*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are three amendments by Mr. Salve. They are not moved. There are three amendments by Mr. Abdul Ghani Dar. Is he moving them?

SHRI ABDUL GHANI DAR: Yes, I move:

Page 6, line 28,—

for "shamefully" *substitute* "knowingly". (18)

Page 6, line 35,—

for "shamefully" *substitute* "purposely". (19)

Page 6, line 37,—

for "show cowardice" *substitute*—"humiliate his country". (20)

जनाब डिप्टी स्पीकर मैं क्लाज 14 पर अपने तीनों अमैंडमेंट्स 18, 19 और 20 मूव कर रहा हूं । चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं कोई इस बारे में स्पीच नहीं करना चाहता । बहुत मुख्तसर में कहना चाहूंगा कि पहले में मैंने यह चाहा कि वर्ड "शेमफुली" की जगह "नोइंग्ली" सब्स्टीच्यूट कर दिया जाये । दूसरे अमैंडमेंट में जो कि लाइन 35 में है मैंने चाहा कि वर्ड "शेमफुली" की जगह शब्द "परपजली" कर दिया जाये । इसी तरह लाइन 37 में वर्ड्स "शो कौवर-डाइस" की जगह "हियुमिलेट हिज कंट्री" कर दिये जाय ।

[श्री अब्दुल गनी]

मैंने श्री चव्हाण को बड़े गौर से सुना जब उन्होंने यह फरमाया कि हमारे आर्मी ऐक्ट में यह अल्फाज मौजूद हैं। अब मेरा कहना है कि वह आर्मी ऐक्ट और उस के वह अल्फाज अंग्रेजों के जमाने के बनाये हुए थे और आज श्री चव्हाण के मुंह से उन की दुहाई देना कुछ सजता नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर श्री चव्हाण कहते हैं कि यह शब्द शेखफुली तो हम ने आर्मी एक्ट से लिया है वहां से हम ने फालो किया है या हमारे अफसरों ने फालो किया है क्योंकि जाहिर है कि चव्हाण साहब को इतने डिटेल में जाने की फुरसत ही कहां होगी, उन्होंने तो दस्तखत कर दिये होंगे हालांकि चव्हाण साहब चौकन्ने जरूर रहे होंगे और इसलिए मेरी चव्हाण साहब से यह रिक्वेस्ट है कि अगर आर्म्ड फोर्सेज ऐक्ट में कोई ऐसी बेवकूफी, गलती या नादानी की बात हुई है तो उसे इस बिल में नहीं दुहराना चाहिए था। मैं चाहूंगा कि वह मेरे इन तीनों अमैंडमेंट्स को मंजूर कर लें और अगर वह ऐसा करते हैं तो उन की बड़ी मेहरबानी होगी।

[جناب ڈپٹی اسپیکر- میں کلاز ۱۴ پر اپنے تینوں امنڈمنٹس ۱۸ - ۱۹ اور ۲۰ موو کر رہا ہوں - چونکہ سمے نہیں ہے اس لئے میں کوئی اس بارے میں اسپیچ نہیں کرنا چاہتا - بہت مختصر میں کہنا چاہونگا کہ پہلے میں میں نے یہ چاہا ہے کہ ورڈ شیم فولی کی جگہ نوانکلی سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے - دوسرے امنڈمنٹ میں جو کہ لائن ۳۵ میں ہے میں نے چاہا ہے کہ ورڈ شیم فولی کی جگہ شیف پریزلی کر دیا جائے - اسی طرح لائن ۳۷ میں ورڈس شیم کورڈائس کی جگہ ہیومیلیایٹ ہز کنٹری کر دئے جائیں -

میں نے شری چوہان کو بڑے غور سے سنا جب انہوں نے یہ فرمایا کے ہمارے آرمی ایکٹ میں یہ الفاظ موجود ہیں - اب میرا کہنا ہے کہ وہ آرمی ایکٹ اور اس کے وہ الفاظ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے تھے اور آج شری چوہان کے منہہ سے ان کی دھائی دینا کچھ سمجھتا نہیں ہے - میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شری چوہان کہتے ہیں کہ یہ شیف شیم فولی تو ہم نے آرمی ایکٹ سے لیا ہے وہاں سے ہم نے فولو کیا ہے یا ہمارے افسروں نے فولو کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ چوہان صاحب کو اتنے ڈیٹیل میں جانے کی فرصت ہی کہاں ہوگی انہوں نے تو دستخط کر دئے ہونگے حالانکہ چوہان صاحب ضرور چوکنے رہے ہونگے اور اس لئے میری چوہان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آرمڈ فورسز ایکٹ میں کوئی ایسی بیوقوفی - غلطی یا نادانی کی بات ہوئی ہے تو اسے اس بل میں نہیں دوہرانا چاہئے تھا - میں چاہونگا کہ وہ میرے ان تینوں امنڈمنٹس کو منظور کر لیں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی -]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister has already explained it. I

shall now put amendments Nos. 18—20 to the vote of the House.

Amendments Nos. 18 to 20 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Salve is not here.

The question is:

"That clause 15 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clauses 16—138 were added to the Bill.

Clause 139—(*Powers and duties conferable and imposable on members of the Force*).

SHRI BALRAJ MADHOK: I am not moving my amendment No. 21. I beg to move:

Page 46,—*after* line 28, *add*—

"Provided that the Border Security Force as such shall not be used to discharge the duties of civil police except in those cases in which the aid of armed forces is sought for the assistance of civil authority". (22)

I would like the Minister to accept this amendment. When I spoke on the Bill, I pointed out that there are two aspects. One is a technical aspect. Here it has been stated in the Bill:

"The Central Government may by general or special order published in the Official Gazette, confer or impose, with the concurrence of the State Government concerned, any of the powers or duties which may be exercised or discharged under a State Act by a police officer upon a member of the Force who, in the opinion of the Central Government, holds a corresponding or higher rank".

Technically, it allows the mixing up of the officers and when you do that, it may be mixing up of officers and sometimes other ranks also of the Border Security Force with the police force that exists in the States. The functions and duties that the police force have to perform and the atmosphere in which they live and work and the kind of psychology that they have and the functions and duties of this force, the kind of work the members of border force have to perform and their whole mental make-up and psychology are different. If you allow the officers of the Border Security Force to be interchanged or brought to the level of State police officers, then either it will harm the State police and more often it will harm the Border Security Force. Therefore, I would say that this kind of interchange will be conducive neither to the efficient functioning of the State police nor to the efficient working of the Border Security Force. If Government want any kind of interchange, it may be interchange of the officers of the armed forces and the border security forces, but there should be no interchange of the officers of this force with the officers of the State police. This is one aspect.

The other aspect was brought out by some other friends also. I do not agree with the line of reasoning they have adopted. But I want to make one thing clear. The Border Security Force must concentrate on the work of border security. That work is itself very important. In fact, for that purpose, it needs further expansion. I do not grudge the expenditure. It may be Rs. 62 crores, it may be Rs. 100 crores. You will have to spend the money and equip the force better, give it the neces-

[Shri Bal Raj Madhok]

sary transport and all that. But then Government say that they can call them to the aid of civil authority as and when they like. They can call even the regular armed forces to the aid of the civil authority. But there are particular conditions and a special way in which they do it. I suggest that in this matter the Border Security Force must be put completely on par with the armed forces. If it is to be called to the aid of the civil authority, it should be only on those conditions and through those processes through which the armed forces are brought to the adi of civil authority. Otherwise, it would create difficulties. This is a force which we want shou'd command the respect of the whole country like the armed forces. Ours is a federal government and there are a number of States in which the Government may not be of the same party to which the Government at the Centre belongs, and there may be some kind of heart-burning also. We know what happened in Jaipur when the question of ministry making was there, which is now being looked into by the Berry Commission. The State Government wanted to precipitate some kind of situation and for that purpose they had already brought 14 companies of the Central Reserve Police and Border Security Police to Jaipur much before the disturbances took place. In that way it was misused, and the people were unhappy. It was not the fault of the Border Security Force. It was the fault entirely of the State Government which had precipitated the situation. To bring the force there and bring it into disrepute will not be correct.

17 hrs.

Therefore, it should be laid down that the force will not be mixed up with the civil police, that its officers will not be interchanged with the civil police, and that whenever it has to be called to the aid of the civil authority, it will be done in the same way, by the same process and under the same conditions in which the armed forces are called to the aid of the civil authority. So, I would request the Home Minister to accept this amendment.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरमीम का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी पिछले मई महीने में फ्रांस में एक बहुत बड़ा विद्यार्थी आन्दोलन और मजदूर आन्दोलन चला था । उन दिनों में शायद आप उसी इलाके में पहुंच गये थे और आपने नजदीक से हुआ आन्दोलन को देखा था । मैं उस वक्त भुज जेल में था । आप ने योरप में इस को देखा होगा कि वहां पर एक महीने भर हड़ताल चली और विद्यार्थियों ने कई दिनों तक वहां हंगामा मचाया, लेकिन कभी भी कोई गोली वहां नहीं चली ।

श्री रणवीर सिंह : हिन्दुस्तान की बात करो ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हिन्दुस्तान दुनियां में ही है मैं क्या करूं ? वहां पर एक भी गोली नहीं चली, कभी पल्टन का इस्तेमाल नही किया गया और न किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया जिस से कि उस देश के लोगों में और वहां की पल्टन में कोई तनाव पैदा हो या गवर्नमेंट के प्रति कोई नाराजगी पैदा हो । हिन्दुस्तान में पिछले बीस वर्षों में क्या रवैया रहा ? कुछ सालों पहले हमारे दल ने इस का एक हिसाब निकाला था कि पन्द्रह सालों में कांग्रेस के राज्य में जितनी गोलियां चलीं और जितने लोग मरे उतने शायद अंग्रेजों के 100 सालों के राज्य में भी नहीं मरे और न ही उतनी गोलियां चलीं ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : आप ने दस महीने के राज्य में उस से ज्यादा गोलियां चलीं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उस का हिसाब आप को बतला दिया जायेगा ।

श्री शिव नारायण : खुदा मियाँ फजीहत, दीगरां नसीहत ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : लेकिन बन्दूक का इस्तेमाल सामान्य नागरिकों के ऊपर, जिन के हाथों में हथियार नहीं हैं, करने का जो सिलसिला हिन्दुस्तान में चला है, उस पर कहीं न कहीं तो रोक लगाना ही चाहिये मैं उम्मीद करता हूं कि श्री चव्हाण इस मामले में नई दिशा के अन्दर एक कदम उठाने का काम जरूर करेंगे ।

अब जो तरमीम यहां पेश की गई है कि बार्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल किसी भी हालत में पुलिस के काम के लिये नहीं किया जायेगा अहम प्रश्न है । बार्डर सक्योरिटी फोर्स के लोगों का इस्तेमाल, जिन के हाथ में हम बन्दूक दे कर हिन्दुस्तान के संरक्षण का काम करना चाहते हैं और सीमा प्रदेश में उन को रखना चाहते हैं, अगर किसी दिन दिल्ली शहर में मजदूरों की हड़ताल को समाप्त करने के लिये या उत्तर प्रदेश अथवा बिहार के इलाके में जहां किसानों का आन्दोलन चलता है उस को दूर करने के लिये किया जाता है, तो यह हमारे खिलाफ बन्दूक का इस्तेमाल किया जाय या नहीं इस का ही नहीं बल्कि जो हमारे पल्टन के लोग हैं उन के मोराल का भी प्रश्न आ जाता है । मैं आप को बतलाऊं कि अभी चन्द दिनों पहले मैं कच्छ में था तब मुझ को जेल में रक्खा गया और बहुत गलत ढंग से रक्खा गया । दो महीने तक जेल में रखने के बाद जो दफा 144 वहां पर लगाई गई थी उस के खिलाफ सबूत दे दिया गया कि वह गलत लगाई गई थी । हम ने यह भी सबूत दे दिया कि जहां पर हम को पकड़ा गया था वह जगह जहां पर दफा 144 लगाई गई थी उस से सात मील दूर थी । तब भी जब हम लोग गिरफ्तार हो रहे थे उस वक्त की एक बात मैं आप को बतलाऊं वहां पर सैंट्रल रिजर्व पुलिस के कई स्वयंसेवक थे और उन में बहुत से जवान थे । हमारे पास हथियार नहीं रहता है न हम हथियार ले कर चलते हैं.....

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): It is not relevant.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह बहुत रिलेवेंट है । मैं मोराल का हवाला उठाना चाहता हूं । जो माननीय सदस्य की बैकग्राउंड है उस में वह इस को नहीं समझ सकेंगे ।

तो जब वह जवान हम को रोक रहे थे और हम सिर्फ अपने शरीर से उनका मुकाबला कर रहे थे तब वह क्या बोले यह आप को मैं बतलाता हूं । वह लोग हम को पहचानते नहीं थे कि हम कौन हैं । वह बोले कि हम को शर्म लग रही है हम क्या करें ? जब हम कार्डन को तोड़ने के लिये बढ़ रहे थे उस वक्त सैंट्रल रिजर्व पुलिस वालों के मुंह से निकली हुई बातों को सुन कर एक क्षण के लिये हमारे मन में यह प्रश्न उठा कि हम कार्डन को तोड़ें या न तोड़ें । जब हम लोग जिन के हाथों में हथियार नहीं थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े थे तथा धक्का मार कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तब उन लोगों की आंखों में आंसू आ गये । वह बोले कि हम को शर्म लगती है हम क्या करें ?

मैं इस लिये यह उदाहरण दे रहा हूं कि यह वह जवान हैं जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान का मुकाबला किया था और उन के भी बहुत से रिश्तेदार देश की सेवा करते हुए मर गये थे । ऐसे लोगों का जब किसी मजदूर आन्दोलन को या किसी किसान आन्दोलन

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

को अथवा हरिजनों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये या नागरिक जीवन को समाप्त करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है तो उन का मोराल खत्म हो जाता है और यह नहीं होना चाहिये ।

इस लिये मैं इस का विरोध करता हूं ।

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने फ्रांस का उदाहरण कोट किया । मैं भी फ्रांस की ही बात कोट करूंगा। फ्रांस के सब से बड़े कमान्डर नेपालियन ने कहा है कि :

"Those who obey can give an order those who do not obey cannot give an order.

वह उन का फरमाना है । जब कभी मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में होती है और जो लोग पाकिस्तान की तरफ या चीन का मुंह देखते हैं और हिन्दुस्तान के लिये खतरा पैदा करते हैं ऐसी दशा में इस तरह की वृत्ति को रोकने के लिये जब भी जरूरत होगी तब इस का इस्तेमाल किया जाएगा । जब भी देश में बेहूदापन होगा तो उस बेहूदापन को रोकने के लिये हम अपनी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे । इस लिये मैं लर्नेड प्रोफेसर से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह अपना अमेंडमेंट न पेश करें । He must send the Force to face the Pakistanis and Chinese.

SHRI BAL RAJ MADHOK: He has not read my amendment.

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not know why he wanted to move his amendment. If his intention is to allow the border security force to be used for internal security purposes—evidently that is what he wants—this provision is meant only for that, not for doing some sort of investigation work, etc.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): On a point of order. In the Gauhati-Shillong road....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not a point of order. We are discussing something else. Let us first finish this.

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not think that really speaking, the amendment is necessary because he accepts the principle that the border security force can be used for any internal security purposes. This provision is meant only for that type of work, not for any other civilian type of police investigation work. Sub-clause 3 of the same clause says that every order made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament. Whenever Government departs from this basic task, they will also have to come before this House and the orders are subject to the scrutiny of the hon. House. I do not think the amendment is necessary.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it amendment No. 21?

SHRI BAL RAJ MADHOK: I had not moved amendment No. 21.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put amendment No. 22 to clause 139 to the vote of the House.

Amendment No. 22 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 139 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 139 was added to the Bill.

Clauses 140 and 141 were added to the Bill.

Clause 142

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is one Government amendment to clause 142.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): Sir, I beg to move:

Page 49, line 10,—

for "appointed" *substitute*—

"appointed or, as the case may be, enrolled" (14)

The purpose of this amendment is to make this Act applicable to those appointed as well as enrolled in the Border Security Force.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

Page 49, line 10,—

for "appointed" *substitute*—

"appointed or, as the case may be, enrolled" (14)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 142, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 142, *as amended, was added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI Y. B. CHAVAN: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): Sir, I might not be misconstrued as supporting my hon. friends across, the Communists or others, in making a slight criticism of this Bill even at this late stage. This Bill ignores the one fact that the border of a country is where its enemies are effective. Today due to many circumstances the border of this country sometimes is in Calcutta itself.

AN HON. MEMBER: It is right here.

SHRI LOBO PRABHU: I accept his amendment—it is right here. Therefore, assuming this, when we want defence against anything like violence, anything which is subversive, we require a Border Force. But, Sir, I would like to say this, that this Border Force seems to cast a reflection both on the army and on the police. There is a feeling that the State police are some kind of a political police, that they are not reliable in these matters. I shall not enter very much into the subject beyond saying this that our State police are many years, almost decades, behind time. They are not properly equipped. They have no motor cycles jeeps, telephones and other equipments of police in other countries. I asked the Home Minister to examine a case where an MLA obtained response from the State police when his neighbour was attacked, after five days. I would say, if you do not want to degrade your State police upgrade them to the level of the Border Police and give them the right equipment. They can deal with these borders in Calcutta or elsewhere arriving there quickly with proper equipment, with proper arms, with cameras etc.

Secondly, I have to pay a tribute to the Border Police. I could probably exceed Mrs. Ila Palchoudhuri in saying they are our defenders, with rendezvous with death at various barricades. But I would further say this that there is a very important and strategic consideration. We are putting the border police at the places where the enemy is likely to penetrate, where the enemy is likely to strike his first blow. One does not put a sponge where the first impact is going to come. My own view is this. Your border police should be behind the line. The army should take the

[Shri Lobo Prabhu]

first shock, not the border police, because if an opening is made by the enemy because of the border police not being strong enough....

SHRI Y. B. CHAVAN: You are an experienced administrator. You should now that the army could not be spread like that.

SHRI LOBO PRABHU: I am not saying that. I am only saying: don't make the border force feel the first impact of the shock. The first shock has to be taken by those who are strong enough to give it back.

श्री चंद्रिका प्रसाद (बलिया): उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने बी० एस० एफ० का संगठन करने के लिए जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इसका मैं हार्दिक समर्थन और स्वागत करता हूं।

जितनी भी बातें इसके सम्बन्ध में यहां कही गई हैं मंत्री महोदय ने उन सब का स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है और वहां से तस्कर का सामान चीन को जाता है और वहां से काफी माल इधर आता भी है। गोरखपुर के रास्ते से बहराइच होते हुए चीनी, चावल, गेहूं आदि नेपाल के रास्ते चीन को जाते हैं। हमारे यहां पूर्व क्षेत्र में शूगर मिलें बहुत हैं। इस वास्ते चीनी वहां से नेपाल होते हुए चीन पहुंच जाती है। चावल भी पहुंच जाता है। अगर इस बिल के अन्दर इस तरह के तस्कर व्यापार की रोकथाम के बारे में व्यवस्था है तब तो ठीक है लेकिन अगर नहीं है तो उसको यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि इन चीजों को उधर जाने से यह रोके। चीनी ट्रांजिस्टर्ज, घड़ियों की हमारी मार्किट में भरमार है और हमारे यहां से चीनी, चावल, गेहूं उधर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तस्कर व्यापार को रोकने का काम भी बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकार क्षेत्र में कर दिया जाए ताकि सीमा से यह जो स्मगलिंग होता है इसको रोका जा सके।

मैं बलिया से आता हूं। आजमगढ़ ब्रिगेडियर उस्मान का जिला है। हमीद गाजीपुर जिले के थे। बलिया, आरा आदि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में संघर्ष के केन्द्र रहे हैं, कुंवर सिंह और मंगल पांडे के जिले रहे हैं। फौज में हमारे क्षेत्र से चार हजार जवान काम करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब इसमें भरती का सवाल आए तो हमारे यहां के लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिये और पहले उनको लिया जाना चाहिये।

बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलिटरी तो नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि सेना से इसका महत्व किसी भी तरह कम नहीं है। जो उनकी ओर से यहां प्रदर्शनी आयोजित की गई थी उसको मैंने देखा है। उसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। और इस फोर्स की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। इस फोर्स ने कच्छ के रण में और बोर्डर पर प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं चाहता हूं कि जिला अधिकारियों को निर्देश दिये जाने चाहियें कि इन लोगों के घर वालों की, इन लोगों के अभिभावकों की सुख सुविधा का वे खयाल रखें। साथ ही इन लोगों को मार्डन वैपंज, जीप्स, हैली कापटर्ज आदि भी दिये जाने चाहियें ताकि देश के बोर्डर्ज की वे रक्षा करने में समर्थ हो सकें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि गृह मंत्री महोदय इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का सुझाव स्वीकार कर लेते। प्रवर समिति में भेजने का अर्थ यह नहीं है कि विधेयक को स्वीकृत करने में

देर लगाई जाए। यदि विधेयक को पास करना जरूरी हो तो प्रवर समिति इसी सत्र के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती थी और सदस्यों को विधेयक की हर एक धारा पर समुचित रीति से विचार करने का अवसर मिल सकता था।

सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमने एक दल का निर्माण किया है और अब उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका निर्देशन करने के लिए एक कानून बना रहे हैं। यह सर्वथा उचित ही है। किसी भी क्षेत्र से इस प्रकार के दल के निर्माण का विरोध नहीं हो सकता। लेकिन गृह मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि सीमा पर सेना रहती है, सुरक्षा दल रहता है और स्थानीय पुलिस रहता है और कभी-कभी इन तीनों के बीच में समन्वय की, सामंजस्य की समस्या खड़ी हो जाती है। विशेषकर जब सीमा की सुरक्षा का दल तस्कर व्यापार को रोकने का प्रयत्न करता है तो फिर उसका स्थानीय पुलिस के साथ संघर्ष में आना अस्वाभाविक नहीं है। उस समय अगर सीमा सुरक्षा दल को सरकार का समर्थन न मिला और उसके सदस्य अपने दायित्व का ठीक तरह से निर्वाह कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई तो जिस उद्देश्य के लिए हम इस दल का निर्माण कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूर्ण करने में बहुत कठिनाइयां पैदा होंगी और आपस में तनाव और खिचाव पैदा होगा जिससे सीमा की सुरक्षा बलशाली होने के बजाय दुर्बल बनेगी।

हम सीमाओं की सुरक्षा के लिये दल बना रहे हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा सीमा की सुरक्षा इस सरकार के संकल्प के ऊपर निर्भर करती है। एक दल हम बनायें, उस का प्रयोग करें, लेकिन समय आने पर सरकार सीमाओं के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण बदल दे, अपनी भूमि दूसरों को देने के लिये तैयार हो जाये, तो इस प्रकार के दल के मनोबल को बनाये नहीं रखा जा सकता। कच्छ में जो कुछ हुआ, श्री जार्ज फरनेन्डीज ने उस की चर्चा की है। मैंने भी वहां जा कर देखा। जो दल कच्छ में पाकिस्तानियों का प्रवेश रोकने के लिये भेजा गया था, उस दल को जिम्मेदारी दी गई हमारे सत्याग्रहियों को रोकने की। अगर पाकिस्तानियों और भारतीय सत्याग्रहियों को एक ही स्तर पर रखा जायेगा और उन दोनों के लिये एक समान दल का उपयोग किया जायेगा, तो इससे कठिनाइयां पैदा होंगी और जनता के मन में भी उस दल के बारे में आशंकायें जागेंगी।

अगर हम सीमा सुरक्षा दल के मनोबल को बनाए रखना चाहते हैं, तो सीमाओं की रक्षा करने का राजनैतिक स्तर पर हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिये। हमारी सीमायें कहां, हैं, अगर हमें यही पता नहीं है, तो उन की रक्षा किस तरह से की जायेगी ? अगर इस के बारे में हम जागरूक नहीं हैं, तो केवल दल बना कर सीमाओं की सुरक्षा नहीं होगी। सीमाओं की रक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं होगी, उनकी रक्षा नई दिल्ली में भी करनी होगी। अभी तक सरकार ने इस बात का प्रमाण नहीं दिया है। मेरा निवेदन है कि दल हम बनायें, उसे सभी प्रकार की सुविधायें दें, लेकिन संकट के समय उस का मनोबल न टूटने पाये, इस की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को लेनी होगी।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय सब से पहले मेरा सुझाव है कि श्री लोबो प्रभु ने जो तकरीर की है, उस को प्रोसीडिंग्ज से एक्सपंज कर दिया जाये, ताकि अगले पांच दस साल में चीनी या पाकिस्तानी यह न कहें कि संसद् के एक जिम्मेदार सदस्य ने यह कहा था कि हमारी सीमा कलकत्ता में है, इस लिये उस से आगे का सब इलाका चीन और पाकिस्तान का हिस्सा है।

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

मुझे फिक्र यह है कि उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों को यह भी पता नहीं है कि हिन्दुस्तान की सीमायें कहां हैं । हम ने कच्छ के बारे में देखा कि जब एक तरफ भुज की एक अदालत में कलक्टर साहब यह गवाही दे रहे थे कि छाड़बेट, कंजरकोट और धारावाणी इस वक्त हमारे अधिकार में हैं, मैं वहां जाता हूं, मेरा जूरिसडिक्शन उन तीनों चौकियों पर है, 1948 से कच्छ के कलक्टर का जूरिसडिक्शन वहां पर चल रहा है और उस से पहले कई बरसों से कच्छ के महाराव का जूरिसडिक्शन वहां पर था, तो दूसरी तरफ हमारे विदेश खाते के एक अंडर सेक्रेटरी ने दिल्ली की किसी अदालत में एफिडेविट दाखिल किया कि छाड़बेट, कंजरकोट और धारावाणी कभी हमारी सीमा नहीं रहे, यह जमीन हमारी नहीं रही ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गम्भीरता से समझलें, क्योंकि इस सदन में इस समय एक बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स बनाने की व्यवस्था हो रही है और बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स उसी देश के काम के लायक होगा, जिस को इस बात की जानकारी होगी कि उस की सीमायें कहां हैं । लेकिन जिस सरकार और जिस देश को अपनी सीमाओं की जानकारी ही नहीं है, उस का बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स क्या करेगा ? यही सब से बड़ा सवाल हमारे सामने है ।

जब देश की सीमाओं के बारे में, काश्मीर की सीमा के बारे में और चीन से लगी सीमा के बारे में, सरकार का दिमाग साफ नहीं है तो फिर इस बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स पर करोड़ों रुपया खर्च करने का क्या मतलब है ? यह प्रश्न मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं । एक तरफ तो यह सरकार सीमाओं के संरक्षण की बात करती है, दूसरी तरफ वह अपनी सीमाओं के बारे में जानकारी नहीं रखती है कि वे कहां पर हैं और तीसरी तरफ उस की तरफ से एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में जो जज साहब नियुक्त हुए, दुनिया के सामने वह उन के दिये गये बयान को झूठा साबित करने की कोशिश करती है यह है इस सरकार की नीतियां ।

अगर इस सरकार को अपने बार्डर के बारे में जानकारी नहीं है, तो यह बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स छाड़बेट, कंजरकोट या धारावाणी के लिये कैसे लड़ेगा ? इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार सब से पहले अपनी सीमाओं को निश्चित करें और फिर बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स की योजना पर ठोस रूप से अमल करे

अन्त में मैं गृह मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । अगर उस का जवाब वह आज दे सकते हैं, तो आज दें, वर्ना एक दो दिन के बाद दें । मुझे पता लगा है कि बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स के एक आफिसर चन्द दिन पहले अपने काम से कच्छ रण जा रहे थे । जिस सड़क से उन्होंने जाना था, उस को वह भूल गये । चूंकि उन को पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी नहीं की जा सकी, इस लिये उन्होंने अपनी पिस्तौल से आत्म-हत्या करली । अगर यह बात सच है तो मंत्री महोदय ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है । अगर इस बारे में जानकारी आज नहीं मिल सकती है, तो वह फिर कभी वह जानकारी दें ।

SHRI NATH PAI (Rajapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a belated, half-hearted measure showing a delayed recognition to one aspect of the complex problem of defence. We would have thought that Shri Chavan, after having listened to the very forceful and convincing pleas that were made yesterday by my friend Shri Somani who made an unusually constructive speech and the resolution moved by Shri Indrajit Gupta and Shri George Fernandes,—I think that was a very reasonable plea—that the

Bill should be referred to the Select Committee, would have acceded to that wish. It is very unfortunate that he has turned down the plea which came from every section of the Opposition. It was not motivated in a spirit of opposition but by way of improving the Bill.

May I point out at this late stage one or two things which he can still afford to look into? Just now, on the eve of the Pakistani aggression in 1965, I happened to be in a village near Palamwala in Akhnoor. I was addressing an *impromptu* meeting. I was sensing the impending danger. There was a small group, and on the tree there was a young lady. She said:

हमने आपको सुना है । अगर आप इजाजत दें, तो अब हम अपनी बात को सुनायें । आप यहां आए, इस से हमें बड़ी खुशी हुई । लेकिन आप यहां के सब बाशिन्दों की तरफ से पार्लियामेंट को कहिये कि हम भाषण नहीं चाहते हैं । हम अपना फर्ज जानते हैं, शायद सरकार और पार्लियामेंट अपना कर्तव्य नहीं जानती है । हम किसी का आशीर्वाद नहीं चाहते हैं; हम हथियार चाहते हैं । हम हिन्दुस्तान की सुरक्षा करने के लिये तैयार हैं । तीन दफा हम उखाड़े गये हैं । हमें हथियार दीजिये । हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे ।

This is a most important thing, and I do not find a sufficient reflection of this spirit of this young lady who represented on this issue not her own views but perhaps the views of those who live on our borders. The border security has assumed new dimensions particularly after the endorsement and encouragement to the Pakistani bellicosity with the arrival of new arms from our friend in Moscow. We are going to get new pinpricks, and it is, therefore, correct that the Government should use the Security Force as the first line of defence, and as he was pointing out, the army will be free to decide, where the major blow comes, what should be done.

Then, I would like to know what Shri Chavan is going to do, to look into this lacuna. What exactly did Shri Indrajit Gupta have in mind when he asked yesterday, whether this force can be called outside India, where, and for what duty. Did he have in mind the duty that the Indian armed forces were performing in Cyprus or in Congo or in South Korea? It is not clear. Therefore, we are asking.

SHRI Y. B. CHAVAN: I have explained that.

SHRI NATH PAI: I tried to get it from him: there was a learned professor to make notes of what he was saying, as you often have your colleagues to do so in your absence. Perhaps it is not very wrong. May I ask one thing? I find that this force will be having all the obligations of the armed forces and all the disadvantages of the police force. They are having the worst of both the worlds: the obligation and duties of the armed forces but not the advantage of the armed forces, but the disadvantage of the police! This has to be looked into.

I am concluding by just asking one question. I think you were present when a very distinguished colleague of yours in Maharashtra whom we had the privilege of having here as an MP, Mr. Kisnave, with your encouragement and perhaps your acquiescence, made a speech which by now has become very memorable. My friend Shri Jagjivan Ram wanted a copy of that speech. Mr. Kisnave talked about the three R's which have become synonymous with ministerial duties—Rum, *Rama*, Rummy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it relevant?

SHRI NATH PAI: Sir, absolutely relevant. I have never been charged with irrelevance. I might have been charged with many sins but I have never been charged with irrelevance. Why are you going to impose such kinds of virtues, that they are to be subject to the so-called prohibition

[Shri Nath Pai]

and abstinence when we know how we leaders are subject to this kind of thing? This is not a charge which I am making. It is a speech made in a very important meeting of the Congress Party, I mean, the one which the Home Minister had the honour and privilege of leading. That was made in his presence. I do not know the veracity of it. I do not know whether it is true or wrong. These 3 Rs are: Rum, *Rama* and Rummy. The fact remains it is no use imposing this false sense of virtue on the boys. I do not believe in imposing virtue.

Then, my another submission is that in recruiting them don't forget those heroes of India, the I.N.A. people. A lot of them can still be invited. Of course, you are right in providing employment to those who are being discharged from the Army. But let priority be given to these I.N.A. people.

SHRI RANDHIR SINGH: This is a good suggestion.

SHRI NATH PAI: Priority will have to be given to the sons of the soil, the local people. The local people will have to take the brunt of the blow. If the enemy's blow is to be blunted before the Army can move in and deliver the counter-blow, may I get an assurance from Mr. Chavan that priority will be given to this thing, that every able-bodied man and woman in the border area will be given the basic training in the use of arms so that they will be the foundation of this Force? I hope Mr. Chavan will not turn a deaf ear to what I am saying. I hope he will take this into consideration. I must also record my protest to his turning down a very constructive proposition of referring this Bill to a Select Committee. I hope I will get a satisfactory reply from him.

17.38 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI Y. B. CHAVAN: Sir, I do not want to reply to many points that were referred to. I must explain that I did not refuse to refer the Bill to a Select Committee. It was not because I was afraid of going to a Select Committee. But I thought it was not necessary to go to a Select Committee because all the questions can be considered here itself.

About one personal reference he made about some speech made in Maharashtra in my presence . . .

SHRI NATH PAI: A colleague of yours.

SHRI Y. B. CHAVAN: Your colleague also. It was a committee meeting of workers of the Congress Party and it was a committee meeting which was meant for self-criticism. It only shows that the Congress Party has got the courage to have self-criticism. I hope if you meet in your party meeting and have the same courage, you will also find interest in Rum, *Rama* and Rummy.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.

17.40 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PRICE OF INDIAN TEA IN INTERNATIONAL MARKETS

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Mr. Speaker, Sir, I would specially deal with marketing structure of Indian tea which has been one of the most important commodities of this country in the field of export trade.

MR. SPEAKER: Now we are having tea!